RNI .NO. MPBIL / 2013/ 54381

संपादकः- डॉ. देवेन्द्र मालवीय

11 वर्ष

दैनिक सद्भावना पाती

...प्राणियों में सद्भावना हो...

www.sadbhawnapaati.com Email: sadbhawnapaatinews@gmail.com इंदौर, गुरुवार ●14 मार्च , 2024 वर्षः-11 अंक - 316 मूल्य -1 रु. कुल पृष्ठ - 8

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व का सिरमौर बनेगा: सीएम

- विदिशा लोकसभा क्षेत्र और भोजपुर विधानसभा क्षेत्र ने देश को नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण जनप्रतिनिधि प्रदान किए
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंडीदीप में 65 करोड़ 55 लाख के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन और शिलान्यास

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विशेष रूप से रहे उपस्थित, मुख्यमंत्री यादव जन आभार यात्रा में हुए शामिल

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भोजपुर स्थित शिवलिंग देश की समृद्ध स्थापत्य कला को अभिव्यक्त करता है। सौभाग्य का विषय है कि विदिशा लोकसभा क्षेत्र को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेई स्व. राजमाता सिंधिया, स्व. श्रीमती सुषमा स्वराज का और भोजपुर विधानसभा क्षेत्र को पूर्व मुख्यमंत्री स्व. सुंदरलाल पटवा का नेतृत्व प्राप्त हुआ। इन क्षेत्रों ने देश को नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण जन-प्रतिनिधि प्रदान किए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की प्रगति के लिए सभी राज्यों को पर्याप्त संसाधन और राशि उपलब्ध करा रहे हैं, उनके नेतृत्व में निश्चित ही भारत विश्व का सिरमौर बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंडीदीप में 65 करोड 53 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विशेष रूप से उपस्थित थे।

भोजपुर क्षेत्र के विकास और जन सुविधाओं से संबंधित मांगे पूर्ण की जाएंगी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल से ही रानी कमलापति देश के सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित हुआ। उनकी इच्छा शक्ति और विकास के प्रति प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरुप ही प्रदेश को केन-बेतवा, पार्वती-काली सिंध-चंबल परियोजना की सौगात प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विधायक सुरेंद्र पटवा द्वारा रखी गई भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास और जन सुविधाओं से संबंधित सभी मांगे पूर्ण की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हितग्राही मूलक योजनाओं के हित लाभ भी वितरित किए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश विकसित हो, प्रदेशवासी आगे बढ़ें और हम जनता की बेहतर सेवा कर सकें, इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री डॉ. यादव की सरकार कार्य कर रही है।

मार्च में गर्मी के तेवर...भोपाल में पहली बार पारा 35 पार

रतलाम-नरसिंहपुर समेत 6 शहरों में तेज गर्मी; मंडला-दमोह सबसे गर्म

भोपाल। मध्यप्रदेश में मार्च में गर्मी तेवर दिखाने लगी है। मंगलवार को कई शहरों में टेम्प्रेचर ज्यादा रहा। भोपाल में इस सीजन में पहली बार दिन का तापमान 35.3 डिग्री दर्ज किया गया। मंडला और दमोह सबसे गर्म रहे। यहां दिन का तापमान 36.6 डिग्री रहा। नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, रतलाम और सिवनी

में भी पारा 36 डिग्री या इससे अधिक रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले दो दिन तक प्रदेश में हल्के बादल छा सकते हैं। इससे टेम्प्रेचर में गिरावट भी हो सकती है। मार्च के दूसरे पखवाड़े में गर्मी के तेवर फिर से तीखे हो सकते हैं। पूर्वी हवाएं चलने से गर्मी का असर बढ़ा है। प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में मंगलवार को पारा सबसे कम 29.4 डिग्री दर्ज किया गया। बाकी सभी शहरों में टेम्प्रेचर 30 डिग्री से अधिक ही दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो मार्च के आखिरी सप्ताह में गर्मी का असर और बढ़ेगा।

गरीब महिलाओं को एक लाख

और नौकरियों में 50 फीसदी आरक्षण

- लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का बड़ा वादा, नारी न्याय गारंटी योजना का ऐलान

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बुधवार को 'नारी न्याय' गारंटी की घोषणा की और कहा कि इससे देश की महिलाओं के लिए समृद्धि का द्वार खुलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक वीडियो जारी कर और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान महाराष्ट्र के धुले में 'नारी न्याय' के तहत पांच कदमों की घोषणा की।

पार्टी की ओर से घोषित 'नारी न्याय' गारंटी के तहत किए गए प्रमुख वादों में हर साल गरीब परिवार की महिला को एक लाख रुपये देना और केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की बात शामिल है।

खरगे ने एक वीडियो जारी कर कहा, कांग्रेस पार्टी आज नारी न्याय गारंटी की घोषणा करती है, इसके तहत कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए देश में एक नया एजेंडा तय करने जा रही है। नारी न्याय गारंटी के अन्तर्गत कांग्रेस पार्टी 5 घोषणाएं कर रही है। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी गारंटी के तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी तथा आधी आबादी -पूरा हक के तहत केंद्र सरकार की नियुक्तियों में आधी हिस्सेदारी महिलाओं को मिलेगी।

इंदौर के इंडस्ट्री हाउस बिल्डिंग की पांचवी मंजिल पर लगी आग, 25 से अधिक लोगों को बाहर निकाला

इंदौर। इंदौर में एबी रोड पर पलासिया क्षेत्र में स्थित इंडस्ट्री हाउस बिल्डिंग की पांचवी मंजिल में बुधवार को अचानक आग लग गई। बिल्डिंग में कई अलग-अलग निजी कार्यालय हैं। अचानक लगी आग तेजी से फैल गई जिसके बाद कर्मचारी जान बचाकर नीचे भागने लगे। इस दौरान ऊपर की मंजिलों में मौजूद कर्मचारी वहीं फस गए। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रसास शुरू किए। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और अंदर फंसे 25 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला। उधर एक व्यक्ति केबल वायरल की सीढ़ी से नीचे उतर आया। पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता, कलेक्टर आशीष सिंह, निगम आयुक्त हर्षिका सिंह भी मौके पर पहुंच गए थे।

एआईएमआईएम बिहार में 11 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार

पटना (एजेंसी)। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार बिहार में लोकसभा की 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीमांचल की चारों सीटों किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया के अलावा इस बार पार्टी बिहार के अन्य इलाकों में भी चुनाव लड़ेगी। अख्तरुल इमान के मुताबिक, पार्टी इस बार दरभंगा, भागलपुर , काराकाट, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर और उजियारपुर में भी अपना उम्मीदवार उतारेगी।

वे हजारों करोड़ के घोटाले कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर में निवेश नहीं कर सके

- विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा-अब सेमी कंडक्टर का हब बनेगा भारत

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर हब बनने की महत्वाकांक्षा पांच दशक पहले पैदा हुई थी, लेकिन पिछली सरकारों ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र की उपेक्षा करते हुए आधुनिक तकनीक में निवेश करने के बजाय हजारों करोड़ रुपये के घोटाले करने का विकल्प चुना। प्रधानमंत्री बुधवार को धोलेरा में

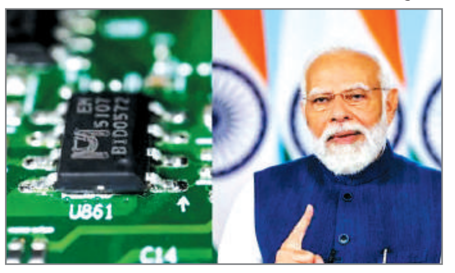

इंडियाज टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये की तीन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सेमीकंडक्टर विनिर्माण का केंद्र बनाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए बुधवार को कहा कि जब भारत वादा करता है, तो वह उसे पूरा भी करता है। मोदी ने तीन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी जिनमें दो गुजरात और एक असम में हैं। इसके बाद उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से लोगों को संबोधित किया। मोदी ने कहा, ''यह एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि हम उज्ज्वल भविष्य की ओर एक मजबूत कदम बढ़ा रहे हैं।''

मोदी सरकार का राजधानी दिल्ली को बड़ा तोहफा

2 नई मेट्रो लाइंस को मोदी कैबिनेट ने दे दी मंजूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के संभवत: आखिरी कैबिनेट बैठक में दिल्ली को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी कैबिनेट ने फेज-4 में दो नए कॉरिडोर को हरी झंडी दी है। इसके तहत 8399 करोड़ की लागत से दो नई मेट्रो लाइन का निर्माण होगा। लाजपत नगर से साकेत जी-ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ के बीच दोनों नए कॉरिडोर का निर्माण होगा। दोनों लाइंस की कुल लंबाई 20 किलोमीटर से ज्यादा है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मेट्रो नेटवर्क का विस्तार भी हुआ और देश की राजधानी में सबसे बड़ा नेटवर्क बनकर खड़ा हुआ है।

लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की दूसरी लिस्ट

10 राज्यों से 72 दिग्गजों को उतारा, नितिन गड़करी नागपुर से आजमाएंगे किस्मत

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा दिन का वक्त नहीं बचा है। बुधवार को भाजपा ने 72 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है।

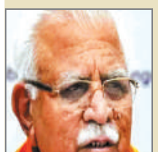

इस लिस्ट में नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर और पीयूष गोयल समेत 72 दिग्गजों के नाम हैं। गडकरी को नागपुर और खट्टर को करनाल लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है। भाजपा ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए जारी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश से पांच नाम फाइनल किए गए हैं। बालाघाट से भारती पारधी, छिंदवाड़ा से विवेक साहू, उज्जैन से अनिल फिरोजिया, धार से साविझी ठाकुर और इंदौर से शंकर लालवानी को टिकट दिया गया है। दूसरी लिस्ट में कर्नाटक राज्य से 20 नाम फाइनल किए हैं। हावेरी से पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को टिकट दिया गया है। चिक्कोडी से अन्नासाहेब शंकर जोल्ले, बागलकोट से पीसी गद्दीगौडर, बीजापुर से रमेश जिगजिणगी, गुलबर्ग से उमेश जी जाधव, बीदर से भगवंत खूबा, कोप्पल से बसवराज क्यावातूर, बेल्लारी से बी श्रीरामुलू, धारवाड़ से प्रल्हाद जोशी, दावणगेरे को गायत्री सिद्देश्वर, शिमोगा बी वाई राघवेंद्र, उजुपी चिकमंगलूर से कोटा श्रीनिवास पुजारी, दक्षिण कन्नड से कैप्टन ब्रिजेश चौटा, तुमकुर से वी सोमन्ना, मैसूर से यदुवीर कृष्णदत्त चामराज, चामराजनगर से एस बालराज, बेंगलुरु ग्रामीण से सीएन मंजूनाथ, बेंगलुरु उत्तर से कुमारी शोभा करंदलाजे, बेंगलुरु सेंट्रल से पीसी मोहन, बेंगलुरु साउथ से तेजस्वी सूर्या को टिकट दिया गया है। दूसरी लिस्ट में दिल्ली से दो नाम फाइनल किए हैं। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को और उत्तर पश्चिम दिल्ली (अनुसूचित जाति) पर योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया है। महाराष्ट्र के लिए भाजपा ने 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। नितिन गडकरी को नागपुर से टिकट दिया गया है। नंदुरबार से हिना विजयकुमार गावित, जलगांव से स्मिता वाघ, रावेर से रक्षा निखिल खडसेस अकोला से अनूप धोत्रे, वर्धा से रामदास चंद्रभानजी, चंद्रपुर से सुधीर

मुंगटीवार, नांदेड़ से प्रतापराव पाटिल, जालना से रावसाहेब दादाराव दानवे, भिवंडी से कपिल मोरेश्वर, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल, मुंबई उत्तर पूर्व से मिहिर कोटेचा, पुणे से मुरलीधर किशन, अहमदनगर से सुजय राधाकृष्ण, बीड़ से पंकजा मुंडे, लातूर से सुधार तुकाराम, माढा से रणजीत सिन्हा हिंदूराव, सांगली से संजयकाका पाटिल, आदिलाबाद से गोजाम नागेश, पेद्दापल्ले से गोमासा श्रीनिवास, मेडक से माधवनेनी रघुनंदन, महबूबनगर से डीके अरुणा, नल्गौड़ा से सईदा रेड्डी और महबूबाबाद से अजमीरा सीताराम नाइक से टिकट दिया गया है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में दोनों लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर और शिमला से सुरेश कश्यप को टिकट दिया गया है। भाजपा ने दूसरी लिस्ट में हरियाणा राज्य से 6 नाम फाइनल किए हैं। करनाल लोकसभा सीट से मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिया है। अंबाला से बंतो कटारिया, सिरसा से अशोक तंवर और फरीदाबाद से कृष्ण पाल गुर्जर को टिकट दिया है। भिवानी-महेंद्रगढ़ से चौधरी धरमबीर सिंह और गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह यादव को टिकट दिया है। दूसरी लिस्ट में गुजरात राज्य से 7 नाम फाइनल किए हैं। अहमदाबाद पूर्व से हसमुख भाई सोमाभाई पटेल को टिकट दिया गया है। वडोदरा से रंजनबेन भट्ट को टिकट दिया है। वहीं, सूरत से मुकेशभाई चंद्रकांत पर भरोसा जताया गया है। साबरकांठा से भीखा जी दुधा जी ठाकोर, भावनगर से निमुबेन बम्भानिया, छोटा उदयपुर से जशु भाई भीलु भाई राठवा वहीं वलसाड से धवल पटेल किस्मत आजमाएंगे।

हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीता विश्वास मत

राज्य विधानसभा में विश्वास मत के पक्ष में पड़े कुल 48 वोट

- जननायक जनता पार्टी के विधायक सदन में नहीं रहे मौजूद

चंडीगढ़ (एजेंसी)। हरियाणा में एक दिन पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है। 12 मार्च को शपथ ग्रहण के बाद एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाया गया था। करीब चार घंटे की चर्चा के बाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई। प्रस्ताव के समर्थन में 48 वोट पड़े।

इस दौरान जननायक जनता पार्टी के विधायक विधायक विधानसभा में मौजूद नहीं रहे। पार्टी की ओर से विधानसभा से गैरहाजिर रहने का व्हिप जारी किया गया था। विधानसभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विश्वास मत रखा। इसके बाद विश्वास मत पर चर्चा का जवाब देते हुए सीएम सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की काफी तारीफ की। उन्होंने पिछले 9 साल में खट्टर सरकार की योजनाओं का जिक्र किया।

अब आर्म्स एक्ट मामले में मुख्तार को उम्र कैद की सजा

- वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला

नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में कैद मुख्तार अंसारी को आर्म्स एक्ट के तहत वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह मामला 1990 में फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल से हथियार लाइसेंस करने से जुड़ा है। तब गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में एक केस इस मामले में दर्ज किया गया था। अदालत ने अंसारी को आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) 467, 468 और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया था। स्टेट की ओर से पेश हुए एडिशनल वकील (क्राइम) मनीष कुमार ने मंगलवार को कहा-मुख्तार अंसारी और एक अन्य शख्स के खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट और गाजीपुर जिले के पुलिस अधीक्षक के जाली हस्ताक्षर के साथ हथियार लाइसेंस हासिल करने की साजिश रची थी।

कमलनाथ के करीबी पूर्व विधायक ने बीजेपी जॉइन की

गंभीर सिंह ने कहा-राहुल गांधी ने अयोध्या न जाकर गलती की; 60 डॉक्टर भी बीजेपी में शामिल

भोपाल। कमलनाथ के करीबी और चौरई से कांग्रेस के पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह ने बुधवार को बीजेपी की सदस्यता ली। भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, बीजेपी की न्यू जॉइनिंग टोली के संयोजक डॉ.नरोत्तम मिश्रा, कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने चौधरी गंभीर सिंह के साथ आए नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। छिंदवाड़ा के अलावा कटनी, मुरैना के कांग्रेस नेताओं और 12 जिलों के 60 डॉक्टरों के साथ 20 फॉर्मासिस्टों ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी जॉइन करने के बाद पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह ने कहा- मैं छिंदवाड़ा में जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहा। 20 साल रघुवंशी समाज का अध्यक्ष भी रहा। मैं प्रदेश कांग्रेस का महासचिव भी रहा हूं। सिवनी, बैतूल का जिला प्रभारी भी रहा।

प्रदेश पाती

दैनिक सद्भावना पाती

इंदौर, गुरुवार 14 मार्च , 2024

संक्षिप्त समाचार

पोषण पखवाड़े के तहत आंगनवाड़ियों में 'खेलो और पढ़ो' कार्यक्रम सम्पन्न

हरदा (निप्र)। पोषण पखवाड़ा अंतर्गत पोषण भी पढ़ाई भी थीम पर खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये ''खेलो व पढ़ो' कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री संजय त्रिपाठी ने बताया कि इस अभियान के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों की दीवारों पर पेंटिंग व पोस्टर के माध्यम से जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। श्री त्रिपाठी ने हरदा के नहाड़िया, सोनतलाई आंगनवाड़ी केन्द्रों का भ्रमण कर पोषण पखवाड़े के तहत आयोजित कार्यक्रमों का जायजा लिया। उन्होने इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया।

महुआखेड़ा में सुंदरकांड पाठ :पट गांव के हनुमान मंदिर में हुआ सुंदरकांड का पाठ

सीहोर(निप्र)। सीहोर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत महुआखेड़ा के ग्राम पट में भक्तो द्वारा सुंदरकांड का आयोजन किया गया। श्री हनुमान मंदिर के नवीन प्राण प्रतिष्ठा से लगातार भक्तों द्वारा 87 सप्ताह से लगातार सुंदर कांड का आयोजन किया जा रहा है। भक्तों द्वारा यहा पर सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी जाती है, सुंदर कांड के बाद प्रसाद वितरण गया। इस दौरान विमल, गौरव राव, अनुराग कुमार समेत कई भक्त उपस्थित रहे।

जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याओं का किया गया निराकरण

रायसेन (निप्र)। कलेक्टर श्री अरविंद दुबे के निर्देशानुसार मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अल्का सिंह द्वारा जनसुनवाई में आए नागरिकों की समस्याओं का निराकरण किया गया। कुछ प्रकरणों में संबंधित विभागों के जिला अधिकारियों को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर निराकरण के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई में अधिकांशतः प्रधानमंत्री आवास, वृद्धावस्था सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विद्युत बिल, आर्थिक सहायता से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

नर्मदापुरम जिले के चार गुंडे-बदमाशों को किया जिलाबदर :माखननगर के वेदांत, ईरानी डेरे के मुख्तार समेत चार बदमाश शामिल

नर्मदापुरम (निप्र)। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले जिले में शांति व्यवस्था बने रहे, इसके लिए अपराधी व बदमाशों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को कलेक्टर सोनिया मीना ने चार गुंडे-बदमाश अपराधियों को जिलाबदर किया। तीन आपराधिक रिकॉर्ड वाले अपराधियों को नर्मदापुरम जिले से 1 वर्ष एवं एक अपराधी को 6 माह के लिए जिलाबदर करने का आदेश जारी किया है। नर्मदापुरम जिला एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से चार अपराधियों को जिलाबदर करने का आदेश जारी किए है। जिलाबदर अपराधियों में माखननगर थाना क्षेत्र के ग्राम आंखमऊ के वेदांत पिता अरविंद यादव (26), इटारसी के पत्ति बाजार ईरानी डेरा निवासी मुख्तार अली पिता सलीम अली ईरानी (30), पिपरिया निवासी आकाश उर्फ नरेंद्र पिता विनोद रघुवंशी (24) को 1 साल व रसूलिया विक्रमनगर रसूलिया निवासी आयुष पिता दिनेश दीवान (26) को 6 माह के लिए जिलाबदर किया है।

प्रदेश में सबसे ज्यादा मंडी टैक्स, किसान-व्यापारी परेशान

नोटिस से खलबली लेकिन सुनवाई कहीं नहीं

इंदौर। चुनावी मौसम आते ही जनप्रतिनिधियों और राजनेताओं को व्यापारियों-किसानों का हित याद आने लगता है। इन दोनों वर्गों का बड़ा मुद्दा मंडी टैक्स में कमी करना है। हर चुनाव में चर्चा में रहने वाला ये मुद्दा अब तक हल नहीं हो सका है। मंडियों में शासन द्वारा सभी प्रकार के अनाज व दलहन जिंसों पर एक प्रतिशत मंडी टैक्स व 20 पैसे निराश्रित शुल्क लिया जा रहा है। ऐसे में व्यापारियों को सौ रुपये की खरीदी पर 1.20 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना कि गुजरात व अन्य राज्यों में आधा प्रतिशत ही टैक्स लिया जा रहा है। प्रदेश में टैक्स घटाकर आधा प्रतिशत करना चाहिए। पहले डेढ़ प्रतिशत टैक्स व 20 पैसे निराश्रित शुल्क लिया जाता था। बड़े वर्ग की इस समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों से व्यापारी-किसान कई बार गुहार लगा चुके हैं लेकिन कहीं से राहत नहीं मिली। 11 सूत्री मांगों को लेकर अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ के आव्हान पर चार सितंबर 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई थी। 18 दिन बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा मंडी टैक्स घटाकर एक प्रतिशत करने पर हड़ताल खत्म की गई थी। दी ग्रेन सीड्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेंद्र चत्तर ने बताया कि मंडी टैक्स कम करने से सभी को फायदा हुआ है। इसे आधा प्रतिशत करने से किसानों व उपभोक्ताओं को और फायदा होगा। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी को लेकर भी विशेष रूप से नोटिस दिए जाते हैं। फरवरी में केंद्र सरकार के जीएसटी विभाग द्वारा सभी व्यापारियों को नोटिस दिया गया है कि वर्ष 2017 से लेकर आज तक का मंडी टैक्स और जीएसटी का विवरण प्रस्तुत करें। व्यापारियों में इसे लेकर हड़कंप मचा हुआ है। इसकी वजह यह है कि पांच साल का रिकार्ड केवल तीन दिन में दे पाना संभव नहीं है। वहीं मंडी व्यापारियों का कहना है कि मंडी टैक्स में कमी नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि मंडी टैक्स के साथ सोयाबीन तिलहन वाली फसल होने के कारण इस पर जीएसटी भी लगाया जाता है। मंडी व्यापारियों को परेशानी हो रही है। मामले में सांसद छतर सिंह दरबार ने कहा कि हाल ही में जीएसटी को लेकर जो नोटिस दिया गया है, उसे लेकर मुझे विशेष रूप से कोई जानकारी नहीं है। मंडी से जुड़े किसान और व्यापारियों के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उनकी व्यवहारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए निश्चित रूप से प्रयास किए जाएंगे।

मंदसौर जिले में कुल नौ मंडिया – लगभग 800 व्यापारी किसानों से उपज खरीदी करते हैं। यहां व्यापारियों से एक प्रश मंडी शुल्क वसूला जा रहा है, जो केवल गुजरात से ज्यादा है। इसके अलावा राजस्थान और अन्य राज्यों में यहां से दुगना मंडी टैक्स वसूला जा रहा है। व्यापारियों का कहना है दूसरे राज्यों से जो उपज खरीद कर लाते हैं, उस पर मंदसौर में भी मंडी टैक्स वसूला जाता है। जबकि मंडी में भी नहीं ले जाते हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र में मंडी व्यापारियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। समय समय पर सरकार तक उनकी बात पहुंचाते रहते हैं।

टैक्स में 31 मार्च तक ही छूट मिलेगी – वर्तमान में कपास खरीदी में व्यापारियों से 70 पैसे प्रति सैकड़ा टैक्स लिया जा रहा है। इसमें 50 पैसे मंडी व 20 प्रतिशत निराश्रित शुल्क लिया जा रहा है। अनाज, दलहन, तिलहन में व्यापारियों से 1.20 पैसे टैक्स लिया जा रहा है। इसमें एक रुपया मंडी व 20 पैसे निराश्रित टैक्स है। व्यापारी संघ का कहना है कि सभी तरह की खरीदी पर 1 रुपये 70 पैसे लिए जा रहे थे। विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकार ने कपास में 1 रुपया कम किया है तो अनाज में 50 पैसे। यह भी 31 मार्च तक के लिए है। विभिन्न समस्याओं के चलते ही खरगोन जिले में संचालित 100 से ज्यादा जीनिंग महाराष्ट्र में चली गई हैं। बड़वानी में भी यही स्थिति है। टैक्स की मार के चलते सेंधवा व खेतिया के कुछ कपास व्यापारियों ने यहां के बजाय महाराष्ट्र में फैक्ट्री स्थापित कर ली है।

निराश्रित शुल्क का कोई औचित्य नहीं – उज्जैन जिले के व्यापारियों को मंडी टैक्स को लेकर परेशानी है। व्यापारियों का कहना है कि तीन महीने पहले मंडी शुल्क 0.50 फीसद कम कर 1 फीसद कर दिया, किंतु 0.20 फीसद लगने वाले निराश्रित शुल्क को यथावत रख दिया। इसका कोई औचित्य नहीं है। यह शुल्क बरसों पहले बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के लिए लगाया गया था। वर्तमान स्थिति में इस शुल्क का उपयोग नहीं हो रहा है। बता दें देश की किसी भी मंडी में निराश्रित शुल्क लागू नहीं है। प्रदेश के व्यापारी, किसान इस शुल्क से मुक्ति चाहते हैं। ताकि व्यापार में अन्य प्रदेशों से प्रतिस्पर्धा कर सके। सांसद इसे लेकर प्रयास करते रहे हैं, मगर सफलता नहीं मिली। इधर झाबुआ जिले के व्यापारियों का कहना है कि मंडियों में सुविधाएं नहीं होने से किसानों व व्यापारियों को दिक्कतें आती हैं।

कपास व्यापारी चिंतित – खंडवा के कपास व्यापारी भी इस बात से चिंचित है कि 31 मार्च के बाद कपास पर भी एक रुपये प्रति सैकड़े के हिसाब से टैक्स वसूला जाने लगेगा। व्यापारियों का कहना है कि चुनाव के दौरान सरकार ने कपास पर टैक्स कम करते हुए इसे 50 रुपये प्रति सैकड़ा किया था लेकिन अब फिर टैक्स बढ़ने नुकसान होगा। मंडी में इस सीजन में कपास की भरपूर आवक हुई है। खंडवा ही नहीं बुरहानपुर और खरगोन जिले से भी किसान यहां कपास लाकर बेच रहे हैं। सीजन के शुरुआती दौर में 300 से 400 वाहन तक कपास नीलाम हुआ लेकिन वर्तमान में औसतन 100 वाहन कपास नीलाम हो रहा है। जनप्रतिनिधियों से यहां भी व्यापारी कई बार अपनी समस्या बता चुके हैं लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ।

भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के 80 से अधिक पदाधिकारी व मुरैना के कांग्रेस नेता

हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का परिवार : वीडी शर्मा

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा, न्यू जॉइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉ. नरोत्तम मिश्रा एवं चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉ. अभिजीत देशमुख के समक्ष बुधवार को कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के 80 से अधिक पदाधिकारी एवं मुरैना के कांग्रेस पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

प्रदेश कार्यालय में बुधवार को कांग्रेस स्वास्थ्य एवं चिकित्सा प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. बसंत राय, ग्वालियर चंबल संभाग प्रभारी डॉ. सिद्धांत दुबे, शिवपुरी में चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉ. नीलेश शर्मा, चिकित्सा प्रकोष्ठ की संयोजक डॉ. ऋचा तिवारी, रीवा टी.आर.एम. कॉलेज पूर्व प्राचार्य डॉ. रामलला शुक्ला, चिकित्सा प्रकोष्ठ के विंध्य संभाग के प्रभारी व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. अमित तिवारी, रीवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉ. दीपनारायण शर्मा, सतना प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉ. दीपक कनौजिया, सागर प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉ. शिवानी वैश्य, महू प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉ. प्रज्ञा चतुर्वेदी, मऊगंज प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉ. कैलाश गुप्ता, रीवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉ. अमर पटेल, रीवा कोविड एसोसिएट अध्यक्ष डॉ. एस.एम. शर्मा, रीवा ब्लॉक अध्यक्ष डॉ. धीरेन्द्र शर्मा, डॉ. टी.के. पाठक, डॉ. मनीष देव वर्मा सहित 12 जिलों के 60 से अधिक चिकित्सकों, 20 से अधिक फार्मासिस्ट एवं प्रबुद्धजनों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेतागणों ने अंगवस्त्र पहनाकर बीजेपी में उनका स्वागत किया।

प्रदेश भाजपा कार्यालय में बुधवार को कांग्रेस कमेटी के पूर्व संभागीय प्रवक्ता सुबोध दुबे, पूर्व प्रदेश सचिव देवेन्द्र मूढोतिया, मुरैना जिला उपाध्यक्ष एवं महिला कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमती शोभा शिवहरे, महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी सोलंकी, प्रकोष्ठ की जिला महामंत्री श्रीमती रामदुलारी मौर्य, प्रकोष्ठ की ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती तुलसा पलैया सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष व वरिष्ठ नेतागणों ने अंगवस्त्र पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया।

जनसुनवाई में 69 आवेदन प्राप्त हुए

विदिशा (निप्र)। नवागत कलेक्टर श्री बुद्धेश कुमार वैद्य के मार्गदर्शन में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में 69 आवेदकों के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर अपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। अपर कलेक्टर श्री अनिल डामोर सहित अन्य के द्वारा मौके पर 30 आवेदनों का निराकरण किया गया है शेष लंबित आवेदनों पर समय सीमा में कार्यवाही कर निराकरण की जानकारी जनआकांक्षा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश संबंधित विभागो के जिलाधिकारियों को दिए गए है। कलेक्टेड्ट के भूतल स्थित सभागार में सम्पन्न हुई जनसुनवाई कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर द्वय श्रीमती शशि मिश्रा, सुश्री निकिता तिवारी, डिप्टी कलेक्टर श्री नितिन जैन, नायब तहसीलदार श्री आकाश महंत समेत विभिन्न विभागो के जिलाधिकारियों ने पंक्तिबद्ध रो में बैठकर आवेदकों से आवेदन प्राप्ति के उपरांत निराकरण की पहल की गई है।

विश्व बर्थ डिफेक्ट माह के तहत क्लबफुट कार्यशाला सम्पन्न

हरदा (निप्र)। विश्व बर्थ डिफेक्ट माह के तहत सोमवार को जिला चिकित्सालय हरदा के सभाकक्ष में क्लबफुट कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सिविल सर्जन डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि क्लबफुट एक जन्मजात दोष है, जिसका निवारण संभव है। जिला चिकित्सालय हरदा में प्रति सप्ताह क्लबफुट वाले बच्चों का उपचार प्रारंभ किया जावेगा। जन्म दोष जन्म के समय मौजूद संरचनात्मक परिवर्तन हैं जो हृदय, मस्तिष्क, पैर जैसे शरीर के लगभग किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकते हैं। वे शरीर के दिखने, काम करने के तरीके या दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। क्लबफुट जन्मजात विकृति है, जिससे हर 800 नवजात में से एक बच्चा प्रभावित होता है। हमारे देश में प्रति वर्ष 33,000 बच्चे इस विकृती के साथ पैदा होते हैं। कार्यशाला में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. कपिल पटेल ने बताया कि क्लबफुट जन्म के 9 दोषों में से एक है, जिसे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत क्लब फुट जैसे 42 जन्मजात बीमारी एवं दोषों की स्क्रीनिंग की जाती है ताकि जल्द से जल्द उचित एवं निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा सके। कार्यशाला में उपस्थित आर.एम.ओ. डॉ. राजेश सतीजा ने बताया कि क्लबफुट का यदि सही समय इलाज नहीं कराया जाए तो बच्चा जीवन भर के लिए विकलांग हो सकता है। कार्यशाला में जिला चिकित्सालय की आयुष चिकित्सा अधिकारी डा मंजू वर्मा, डॉ परमानंद छलोत्रे, आडियोलॉजिस्ट नीरज मालवीय सहित नर्सिंग ऑफिसर मौजूद रहे।

कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष सीहोर में उपस्थित पटवारी एवं सहायक कृषि विस्तार अधिकारियों को नियुक्ति-पत्र प्रदान किये

सीहोर (निप्र)। राज्य स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शामिल हुए। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा सीहोर जिले के 6 पटवारी तथा 6 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। कार्यक्रम का जिले में सीधा प्रसारण प्रदेश के साथ ही सीहोर जिले में भी देखा व सुना गया । कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में उपस्थित पटवारी तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने नवनियुक्त पटवारी तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों से कहा है कि शासकीय सेवा का मतलब जनता की सेवा है। नियुक्ति मिलने के बाद कर्तव्य, जिम्मेदारी का भाव मन में हो क्योंकि हम पर प्रदेश की प्रगति और विकास निर्भर है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री वृंदावन सिंह तथा एसएलआर स्मिता भूषण, कृषि विभाग की सहायक संचालक हुदा खलील भी उपस्थित रहे।

नियुक्ति पत्र मिलने पर श्रद्धा ने मुख्यमंत्री डॉ यादव को दिया धन्यवाद

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश भर के चयनित हुए अभ्यार्थियों को भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र प्रदान किए । कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में उपस्थित नव नियुक्त पटवारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए । ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर चयनित होने के बाद अपना नियुक्ति पत्र लेने आई सीहोर जिले के ग्राम बढ़ियाखेड़ी निवासी श्रद्धा तिवारी ने प्रशन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को धन्यवाद दिया । श्रद्धा तिवारी को कृषि विकास एवं किसान कल्याण विकास विभाग सीहोर में पदस्थ किया गया है ।

जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक संपन्न

विदिशा (निप्र)। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी की अध्यक्षता में जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक आज जि.पं. के सभागार कक्ष में संपन्न होने के साथ-साथ सामान्य प्रशासन समिति की बैठक भी हुई जिसमें गुलरखेड़ी में पेयजल संकट को दूर करने हेतु टैंकरों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति के प्रबंध सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए इसके अलावा संपूर्ण जिले में जिन स्थानों पर गौशालाएं बनकर पूर्ण हो गई हैं उन गोशालाओं में मवेशियों को पहुंचाए जाने के प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं, गौशालाओं में पर्याप्त बिजली आपूर्ति व पेयजल के प्रबंध सुनिश्चित हों के निर्देश बैठक में दिए गए हैं। उक्त बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को उक्त कार्यों के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिए हैं।

बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री दरियाब सिंह कुर्मी, जनपद पंचायत के सदस्य गणों के अलावा जिला पंचायत के अतिरिक्त सीईओ श्री पंकज जैन समेत अन्य विभागों के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में जिन पंचायतों में अत्यधिक जलसंकट है उन पंचायतों को पेयजल का परिवहन करने की अनुमति दिए जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को सख्त निर्देश दिए गए कि जिले की किसी भी ग्राम पंचायत में सड़कों को जेसीबी मशीन द्वारा ना खोदा जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की भर्ती में जो अपीलें की गई हैं उनकी सुनवाई त्वरित करके निराकरण किया जाए। साथ ही साथ ग्रीष्मकालीन सत्र को ध्यानगत रखते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बिजली फॉल्ट या शार्ट सर्किट के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों में आग लगने की घटनाएं होती हैं जिस पर विराम लगाए जाने हेतु अभी से आवश्यक तैयारी करते हुए बिजली के लूज तारों का मेंटेनेंस कराया जाए।

बरेली में स्कूल बस ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर :ट्रैक्टर चालक सहित तीन छात्र घायल, बस ड्राइवर पर केस दर्ज

रायसेन (निप्र)। रायसेन के जिले बरेली थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक निजी स्कूल बस ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मारी। जिसमें ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे भोपाल रेफर किया गया। वहीं बस में बैठे छात्र घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बरेली के डैफोडिल पब्लिक स्कूल की बस सुबह छात्र- छात्राओं को लेकर स्कूल जा रही थी। इस दौरान बस ड्राइवर ने लापरवाही पूर्व बस चलाते हुए ट्रैक्टर में पीछे से टक्कर मार दी। जिसमें ट्रैक्टर चालक संतोष नायक बुरी तरह घायल हो गया। जिसे प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर कर दिया गया है। वहीं बरेली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल तीन छात्र-छात्राओं को बरेली सिविल अस्पताल पहुंचाया।

नर्मदापुरम में आदिवासियों ने रैली निकाल दी चेतावनी

सात दिन में पट्टे के आदेश न हुए तो लेंगे हाईकोर्ट की शरण

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम में वनवासी कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ की जिला ईकाई के तत्वावधान में आदिवासी महिला-पुरुषों ने मंगलवार को धरना दिया। पीपल चौक पर धरना देकर सभी लोग रैली निकाल कलेक्ट्रेट गेट पहुंचे। वहां राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप चेतावनी दी कि 2006 के पूर्व वन एवं राजस्व भूमि में निवासरत, खेती करने वाले व्यक्तियों को पट्टा देने के आदेश 7 दिन में जारी हो, वरना वनवासी कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ अपने अधिकार व हक के लिए हाईकोर्ट की शरण लेगा। प्रदेश मंत्री, जिला प्रभारी जितेंद्र सिंह उइके ने बताया 2002 से 2024 तक राजस्व एवं माखननगर तहसील के ग्राम खकरापुरा, डांगपुरा में 57 परिवार, डोब में 56 परिवारों को भूमि आवासीय एवं कृषि भूमि का पट्टा अधिकार नहीं दिया गया। घोंघरीखेड़ा के 27 परिवारों को आवासीय पट्टे एवं कृषि भूमि का अधिकार पट्टा दिया गया, लेकिन उन परिवार को मप्र शासन की योजनाओं का कृषक सम्माननिधिका लाभ एवं केसीसी पट्टे का लाभ नहीं दिया जा रहा। जिससे जनजाति वर्ग के अधिकारों का हनन किया गया है। संभाग आयुक्त, कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ से निवेदन किया कि 7 दिनों के भीतर पट्टे वितरण कराने के आदेश जारी करें, नहीं तो उच्च न्यायालय जाएंगे। ज्ञापन देने के दौरान वनवासी कृषि एवम् ग्रामीण मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री जिला प्रभारी जितेंद्रसिंह उइके, जिला अध्यक्ष लक्ष्मण लोभे, जिला महामंत्री सत्यम धुर्वे, जिला उपाध्यक्ष संतोष उइके, जिला जिला मंत्री आरती शीलू, जिला कोषाध्यक्ष करण सिंह एवं संघ के समस्त ब्लाकों के कार्यकर्ता उपस्थित रहें।

दैनिक सद्भावना पाती

इंदौर पाती

...प्राणियों में सद्भावना हो...

इंदौर, गुरुवार 14 मार्च , 2024

चिंगारी गैंग की हरकत, नशे में टामी-बेल्ट रगड़ते निकले

इंदौर। बाइक सवारों का नशे में चिंगारी निकालते हुए वीडियो सामने आया है। युवक बुलेट पर जा रहे है और उनके हाथ में टामी–बेल्ट है। लोगों ने इनका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जारी किया है ।वीडियो कलेक्टोरेट से महू नाका की तरफ़ का है। शाजापुर पासिंग बुलेट पर तीन युवक जा रहे थे। एक तो नशे में झूम रहा था। उसके हाथ में लोहे की टामी है। उस टामी को सड़क पर रगड़ता है जिससे चिंगारी निकलती है। इस दौरान आस–पास चलने वाले वाहन चालक घबरा जाते हैं। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्रैफ़िक डीसीपी मनीष अग्रवाल के मुताबिक, बाइक (एमपी 42एमआर 7107) का नंबर पता चला है। पुलिसकर्मी मामले की जांच कर रहे है।

इंदौर की पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष जया तिवारी भाजपा में शामिल

इंदौर। इंदौर की पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष जया तिवारी बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, उन्हें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा ने सदस्यता दिलाई। बुधवार को भोपाल के भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नागेंद्र सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू ने जया तिवारी को भाजपा का दुपट्टा पहनाकर सदस्यता दिलाई ।तिवारी इंदौर में पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी है और काफी समय से महिला कांग्रेस में सक्रिय थी अब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। तिवारी ने कहा कि अयोध्या श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण जब कांग्रेस ने ठुकराया तो मुझे बहुत बुरा लगा इसलिए मैने कांग्रेस छोड़ दी है। अब भाजपा में राष्ट्र सेवा के लिए कार्य करूंगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कई भाजपा महिला कार्यकर्ता मौजूद रही।

नेमावर रोड चौड़ीकरण की तैयारी शुरू

इन्दौर। मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआरडीसी) ने नेमावर रोड चौड़ीकरण की तैयारी शुरू की है। विभाग द्वारा करीब 29 किलोमीटर लंबे हिस्से को फोर लेन में बदलने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई जा रही है। माना जा रहा है कि अगले तीन महीने में डीपीआर तैयार हो जाएगी। उसके बाद इसकी औपचारिक मंजूरी की प्रक्रिया होगी। यह रोड बायपास के देवगुराडिय़ा जंक्शन से करनावद की तरफ बनाया जाएगा। यह वह हिस्सा है, जो इंदौर–राघौगढ़ ग्रीन फील्ड हाईवे बनने के बाद नेशनल हाईवे से डिनोटिफाई होगा। तब इसका रखरखाव एमपीआरडीसी के पास आएगा। एमपीआरडीसी का मानना है कि नया हाईवे बनने के बावजूद नेमावर रोड की उपयोगिता बनी रहेगी। जिन वाहन चालकों को खलघाट या अकोला हाईवे से आना–जाना है, वे देवगुराडिय़ा होकर ही गुजरेंगे। इसके अलावा इस क्षेत्र का आंतरिक ट्रैफिक तो रहेगा ही, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसका चौड़ीकरण जरूरी है, क्योंकि फिलहाल यह केवल दो–ढाई लेन चौड़ा ही बना है। चौड़ीकरण के लिए सडक़ के दोनों ओर अतिक्रमण, बाधक निर्माण, पेड़, बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर हटाना होंगे।

इंदौर के किसानों को करना होगा सप्ताह का इंतजार

इंदौर। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में देरी होने से किसान नाराज हैं। वहीं 6 साल पुराना बोनस किसानों को अभी तक नहीं मिला। फिर से राज्य सरकार ने 125 रुपए गेहूं पर बोनस देने का ऐलान किया तो किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है। इंदौर जिले में 80 फीसदी गेहूं कट चुका है। किसानों को मंडियों में गेहूं के दाम समर्थन मूल्य से नीचे कम मिल रहे हैं। वह फरवरी के आखिर से ही समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए तारीखों के ऐलान का इंतजार कर रहा है। अब जाकर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से आदेश जारी हुआ है, जिसमें खंडवा–खरगोन में 15 मार्च और इंदौर जिले में 20 मार्च से गेहूं की सरकारी खरीदी शुरू होगी ।इंदौर जिले में 97 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। विभाग की ओर से दावा किया गया कि इस बार 40000 किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन कराया है। सरकार की ओर से 2 दिन पहले गेहूं के समर्थन मूल्य 2275 रुपए के साथ राज्य सरकार की ओर से 125 रुपए बोनस किसानों को दिया जाएगा। इस प्रकार किसानों को प्रति क्विंटल 2400 रुपए गेहूं सरकार को बेचने के दौरान प्राप्त होंगे। किसानों में आक्रोश इस बात को लेकर आया कि 2018 में सरकार ने 160 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की थी, लेकिन वह आज तक नहीं दिया गया। किसान मजदूर सेवा के बबलू यादव, दूलेसिंह राठौर ने बताया कि लगातार सरकार को पुराना बकाया बोनस देने की गुहार लगाई जा रही है।

श्रमिकों को 25 प्रतिशत अधिक मजदूरी मिलेगी, नया वेतनमान होगा जारी

इंदौर। औद्योगिक और असंगठित श्रमिकों को एक अप्रैल से 25 प्रतिशत अधिक मजदूरी मिलेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश एक अप्रैल से लागू होगा। बता दें कि 2014 के बाद प्रदेश में पहली बार मजदूरों का मजदूरी का पुनरीक्षण किया गया है।जानकारी के अनुसार, प्रचलित न्यूनतम वेतन की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। नई न्यूनतम वेतन दरों के प्रभावशील होने पर अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 9 हजार 575 रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। इसी तरह अर्द्धकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 10 हजार 571 रुपये प्रतिमाह होगा। कुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 12 हजार 294 जबकि उच्च कुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 13 हजार 919 रुपये प्रतिमाह हो जाएगा।

श्रमिकों की वेतन दरें लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी 2019 से जून 2019 के आंकड़ों के औसत पर आधारित है। इसके साथ ही कृषि श्रमिकों को देय प्रचलित न्यूनतम वेतन की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि तथा लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के आधार पर एक अक्टूबर 2019 से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को न्यूनतम वेतन में जोड़कर नई न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई है।

नई न्यूनतम वेतन दरों के प्रभावशील होने पर खेती किसानी से जुड़े मजदूरों को न्यूनतम वेतन 7 हजार 660 रुपये प्रतिमाह मिलने लगेगा। इसी प्रकार बीड़ी श्रमिकों एवं अगरबत्ती श्रमिकों के वेतन में भी देय प्रचलित न्यूनतम वेतन की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

भाजपा इंदौर में तैयार करेगी लोकसभा सीटों की रणनीति

इंदौर। भाजपा की लोकसभा चुनाव में मालवा-निमाड़ की सीटों पर कब्जा बरकरार रखने की रणनीति इंदौर से तय होगी। इंदौर के मुख्य चुनाव कार्यालय में न सिर्फ केंद्र और प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी बैठकें लेंगे, बल्कि वे यहीं से अन्य लोकसभा सीटों के लिए दिशा निर्देश और रणनीति भी जारी करेंगे।इंदौर कार्यालय के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव बुधवार 13 मार्च को खुद इंदौर आ रहे हैं। शाम करीब 5.30 बजे कार्यक्रम होगा। चुनाव कार्यालय में बनाए जाने वाले मीडिया रूम में पल-पल का अपडेट उपलब्ध रहेगा। पार्टी ने यहीं वार रूम भी बनाया है। इसके अलावा वरिष्ठ नेताओं द्वारा ली जाने वाली गोपनीय बैठकों के लिए एक विशेष सभाकक्ष तैयार किया गया है। पार्टी कार्यालय की तीसरी मंजिल पर बनाया गया यह गोपनीय सभाकक्ष हाई टेक है। इस वजह से इंदौर में बनाया गया मुख्य चुनाव कार्यालय

इंदौर देश के लगभग मध्य में स्थित है। यहां से दिल्ली सहित अन्य शहरों की कनेक्टिविटी बहुत आसान है। इंदौर एयरपोर्ट से रोजाना 100 से ज्यादा उड़ाने देश के अन्य शहरों के लिए उड़ती हैं। प्रदेश के प्रमुख नेताओं का इंदौर आना-जाना लगा रहता है। मीडिया प्रभारी रितेश तिवारी, नितिन द्विवेदी ने बताया कि इंदौर में बनाए गए लोकसभा चुनाव कार्यालय के लिए कार्यालय प्रभारी घनश्याम शेर को बनाया गया है। इंदौर लोकसभा प्रभारी सुमेर सिंह सोलंकी, लोकसभा संयोजक रवि रावलिया, सह संयोजक गोपाल गोयल होंगे।

तिवारी ने बताया कि हाई टेक कार्यालय में सूचनाओं का लगातार आदान प्रदान होगा। हमारी व्यवस्था इस तरह से बनाई गई है कि हम एक दिन में पांच हजार से ज्यादा सूचनाएं कार्यकर्ताओं तक पहुंचा सकते हैं। बुधवार को आयोजित कार्यक्रम के लिए थ्री स्टेप मंच बनाया गया है। 60 से ज्यादा वरिष्ठ पदाधिकारी के बैठने की व्यवस्था मंच पर रहेगी।

इंदौर को अन्य शहरों से फोरलेन के माध्यम से जोड़ने वाले दो प्रमुख मार्ग बनाने की योजना नहीं हो सकी पूरी

मार्गों पर निर्माण पूरा होने में लगेगा दो साल का समय

इंदौर। शहर को अन्य शहरों से फोरलेन के माध्यम से जोड़ने वाले दो प्रमुख मार्ग बनाने की योजना पूरी नहीं हो सकी है। इंदौर-खंडवा-एदलाबाद और इंदौर-हरदा-बैतूल मार्ग को टू लेन से फोर लेन किया जाना है। केंद्रीय योजना के तहत बनाए जाने वाले दोनों मार्गों पर निर्माण पूरा होने में करीब दो साल का समय लगेगा। इंदौर-हरदा-बैतूल मार्ग को फोर लेन करने की कवायद करीब आठ साल से चल रही है। कई बार इसकी घोषणा हुई, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ पाया। करीब 272 किमी लंबे इंदौर-हरदा-बैतूल हाईवे के हरदा से इंदौर की तरफ वाले काम को गत वर्ष से गति मिली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अलग-अलग चरणों में इसका निर्माण किया जा रहा है। पहले चरण में बैतूल से हरदा तक का काम लगभग पूरा हो चुका है।

हरदा से कन्नौद तक सड़क निर्माण का काम जारी है। फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत इंदौर से करनावद (राघोगढ़) ग्रीनफील्ड हाईवे का काम भी शुरू हो गया है। बॉयपास स्थित एमआर-10 चौराहे से राघोगढ़ तक 26.65 किमी सड़क निर्माण की लागत 358 करोड़ रुपये है। इंदौर की तरफ से काम शुरू हो चुका है। अभी दो साल का समय इंदौर से हरदा तक फोर लेने का काम पूरा होने में लगेगा। एनएचएआई द्वारा 216 किमी लंबे इंदौर-खंडवा-एदलाबाद मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। कई बार इसे फोरलेन करने की घोषणा हुई, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। गत वर्ष भूमिपूजन के बाद का शुरू किया गया। सड़क के अलाइनमेंट में कई बार बदलाव के कारण काम देरी से शुरू हुआ। यह सड़क पांच चरणों में बनाई जा रही है। पहले चरण में तेजाजी नगर से बलवाड़ा तक 33 किमी सड़क का निर्माण होगा। इसके बाद बलवाड़ा से धनगांव तक 40 किमी हिस्से में सड़क बनेगी। कुल लागत 950 करोड़ रुपये है। इंदौर के आसपास 140 किमी लंबा रिंग रोड बनाने की योजना सालों पहले तैयार की गई थी, ताकि अन्य शहरों से आने वाले वाहन शहर से बाहर से निकल सके। सालों तक इसकी योजना बनती रही, लेकिन काम शुरू नहीं हो सका। अब इसकी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 64 किमी लंबी पश्चिमी रिंग रोड का निर्माण 2000 हजार करोड़ रुपये की लागत से होगा। पहले चरण में 34 किमी और दूसरे चरण में 30 किमी हिस्सा बनेगा। 77 किमी लंबी पूर्वी रिंग रोड का निर्माण तीन चरण में किया जाएगा। इसके टेंडर की प्रक्रिया जारी है।

लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू, नेहरू स्टेडियम के स्ट्रांग रूम में होगा बदलाव

इंदौर। इंदौर जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। नेहरू स्टेडियम में मतदान और मतगणना की प्रक्रिया के लिए व्यवस्थाएं जुटाई जा रही है। यहां बनाए जाने वाले स्टॉक रुम में भी बदलाव होगा। पोलिंग बूथ के अनुसार स्ट्रांग रूम के कक्ष तय किए जाएंगे, ताकि ईवीएम और अन्य सामग्री रखने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।विधानसभा चुनाव में छोटे कक्ष के कारण कई विधानसभा क्षेत्र में मतदान सामग्री और मतगणना के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ा था। विधानसभा क्षेत्र इंदौर पांच का स्ट्रांग रूम बड़े कक्षा में बनाया जाएगा। वहीं राऊ विधानसभा क्षेत्र का स्ट्रांग रूम भी बदलेगा।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने नेहरू स्टेडियम पहुंचकर लोकसभा निर्वाचन-2024 की तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर डीसीपी ट्रॉफिक मनीष कुमार अग्रवाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा अपर कलेक्टर राजेन्द्र रघुवंशी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर आशीष सिंह ने इस मौके पर लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदान दलों को सामग्री के वितरण व्यवस्था, स्ट्रांग रूम व्यवस्था, मतगणना कक्षों की व्यवस्था आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन की सभी तैयारियां निर्वाचन आयोग द्वारा तय दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय पर की जाए।नेहरू स्टेडियम में ही प्रचार सामग्री को लेकर राजनीति दलों की बैठक हुई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह लोकसभा निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाले विभिन्न सामग्रियों, साधनों के बाजार दर निर्धारण के लिए आयोजित बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारी भी मौजूद थे।

बैठक में निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली विभिन्न सामग्रियों, साधनों के बाजार दर का निर्धारण किया गया। इसमें टेंट संबंधी सामग्री, कैटरिंग सामान, पंखा, कूलर, एसी. साउंड सिस्टम, लाइट, प्रचार सामग्री, बैंड, ढोलक, फ्लावर डेकोरेशन, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, जलपान, स्वल्पाहार, भोजन, फल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी आदि का निर्धारण किया गया।

कैलाश विजयवर्गीय ने पार्षदों को दी हिदायत

इंदौर ने हमें बहुत दिया है, शहर का कर्ज चुकाना हमारी जिम्मेदारी

इंदौर। नगर निगम परिसर में आयोजित 24 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों के भूमिपूजन और सात करोड़ रुपये के विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पार्षदों को हिदायत दे दी। उन्होंने कहा कि इंदौर ने हमें बहुत दिया है। शहर का कर्ज चुकाना हमारी जिम्मेदारी है। हम सब खुशकिस्मत हैं कि हमें शहरवासियों की जिंदगी को आसान करने की जिम्मेदारी मिली है। कई शहरों में मुझे पार्षदों के बारे में शिकायत मिलती है कि कोई बिल्डिंग बनती है तो वे इंच-टेप लेकर उसे नापने पहुंच जाते हैं। इंदौर के पार्षद इन बातों से बचें। हालांकि हमारे शहर की परंपरा भी यह नहीं हैं।विजयवर्गीय ने कहा कि दो वर्ष पहले कचरे से कंचन प्लांट लगाया गया था। तब कहा गया था कि इससे नगर निगम को आय होगी, लेकिन आय नहीं हो रही है। हम सबको मिलकर उस प्रोजेक्ट की समीक्षा करनी होगी। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा 80 नवीन स्वच्छता वाहन, दीनदयाल रसोई योजना के तहत चार चलित रसोई वाहन, छह मोक्ष रथ सुविधा का भी शुभारंभ किया गया।

विजयवर्गीय ने कहा कि शहर का यातायात ठीक नहीं है। उन्होंने महापौर पुष्यमित्र भार्गव से कहा कि एक सड़क को शहर सिग्नल फ्री बनाए, जहां जरूरत हो वहां अंडरपास, ब्रिज बनाएं, लेकिन सिग्नल कम से कम हों। महापौर ने समारोह में बताया कि निगम आत्मनिर्भर बनने के लिए कई प्रयास कर रहा है। जलकर के मामले में वन टाइम सेटलमेंट योजना लाए हैं। महापौर के रूप में 22 साल पहले कैलाश विजयवर्गीय निगम मुख्यालय आते-जाते रहे, लेकिन मंगलवार को उन्होंने वर्षों बाद यहां कदम रखा था। मंच पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि 22 साल बाद आया हूं। इसके बाद भी मुझसे शव वाहन का उद्घाटन करवाया जा रहा है। विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि इतने वर्ष मुझे आने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी, क्योकि इशारों में ही काम हो जाते थे। कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगमायुक्त हर्षिका सिंह, विधायक महेंद्र हार्डिया, रमेश मेंदोला, मधु वर्मा, मालिनी गौड़, गोलु शुक्ला, महापौर परिषद सदस्य राजेंद्र राठौर, अभिषेक शर्मा, मनीष शर्मा, निरंजनसिंह चौहान, राकेश जैन, जीतू यादव, उपस्थित थे। संचालन सचेतक कमल वाघेला ने किया।

सरवटे से गंगवाल सड़क का काम नए सिरे से शुरू करने की तैयारी में निगम, प्रस्ताव तैयार

साढ़े 11 करोड़ रुपए होंगे खर्च

इंदौर। वर्षों से आधा अधूरे पड़े सरवटे से गंगवाल सड़क का काम नगर निगम अपने स्तर पर नए सिरे से शुरू करने की तैयारी में है। प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। साढ़े 11 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चंद्रभागा पुल के पास से 60 फीट चौड़ी नई सड़क इसी के तहत बनाई जाएगी, जो हरसिद्धि झोनल और सीपी शेखर नगर उद्यान के सामने तक रहेगी। इससे वाहन चालक हरसिद्धि और मच्छी बाजार सुगमता से जा सकेंगे। नगर निगम ने वर्ष 2016 में सरवटे क्षेत्र से सरवटे टू गंगवाल सडक़ का काम शुरू कराया था। इस क्षेत्र से काम शुरू कराने के पीछे यह मंशा थी कि उक्त रूट पर बाधाएं कम है और काम तेजी से हो सकेगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं हो पाया और केवल सरवटे से लेकर सिर्फ हाथीपाला चौराहे तक ही सड़क बन पाई। दूसरी ओर रावला और चंद्रभागा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बाधाएं होने के कारण सड़क चंद्रभागा जूनी इन्दौर से मच्छी बाजार तक आधी-अधूरी पड़ी है। मच्छी बाजार से लेकर कड़ावघाट, दरगाह चौराहा, बियाबानी होते हुए गंगवाल बस स्टैंड तक सडक़ पूरी तरह बनकर तैयार है। अब इस सड़क को निगम साढ़े 11 करोड़ की लागत से बनाने की तैयारी में है और इसके नए सिरे से टेंडर जारी करने के प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। आने वाले 10 से 15 दिनों में टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उक्त सड़क की एक लेन चंद्रभागा पुल के पास से हरसिद्धि झोनल कार्यालय की ओर होते हुए सीपी शेखर उद्यान के सामने तक बनेगी। यह सडक़ 60 फीट चौड़ी रहेगी और इसका प्रस्ताव मास्टर प्लान में भी है। इस सडक़ के हिस्से से कई वाहन चालकों को यह सुविधा मिलेगी कि अब तक उन्हें गौतमपुरा से पंढरीनाथ होते हुए हरसिद्धि पुल तक जाना पड़ता था। अब वाहन चालक सीधे चंद्रभागा से उक्त सडक़ का उपयोग कर हरसिद्धि पुल तक पहुंच सकेंगे।

गौतमपुरा से पंढरीनाथ जाने वाली कंबल वाली सडक़ आए दिन दोनों ओर से वाहनों के आने के कारण जाम रहती है। कई बार तो वहां जाम के हालात ऐसे होते है कि इसका असर मच्छी बाजार,पंढरीनाथ, कबूतरखाना, गौतमपुरा और हरसिद्धि जाने वाले मार्गों पर भी पड़ता है, क्योंकि पंढरीनाथ मुख्य चौराहे पर जाम का मुख्य केंद्र रहता है और ऐसे में आसपास के मार्गों से आने वाले वाहन चालक भी वहां उलझ जाते हैं। वर्तमान में उक्त सडक़ कई हिस्सों में 25 से 30 फीट चौड़ी ही है। अब इसे 40 फीट चौड़ी बनाए जाने की तैयारी हैं और बाधाएं चिन्हित कर सडक़ चौड़ीकरण करवाया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा इंदौर संभाग में गेहूं उपार्जन की समीक्षा

इंदौर। मध्यप्रदेश की अतिरिक्त मुख्य सचिव (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग) श्रीमती स्मिता भारद्वाज ने रेसीडेंसी कोठी में संभाग के सभी जिला कलेक्टरों और अन्य संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में संभागायुक्त इंदौर दीपक सिंह ने बताया कि संभाग के सभी ज़िलों में गेहूं खरीदी केन्द्रों का निर्धारण हो गया है और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती स्मिता भारद्वाज ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि गेहूं खरीदी से संबंधित सभी विभागों को रबी उपार्जन के नवीन प्रावधानों से अवगत कराएँ। गेहूं खरीदी में किसानों को मध्यप्रदेश सरकार ने अतिरिक्त रूप से बोनस देने का निर्णय लिया है, जिसका भुगतान उनके खाते में किया जाएगा, इसकी जानकारी भी किसानों को दी जाए। उन्होंने कहा कि गेहूं ख़रीदी के लिए नियुक्त सर्वेयर का प्रशिक्षण एवं परीक्षा निर्धारित समय पर कराएं। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों से कहा कि आने वाले समय में निर्वाचन में सभी की व्यस्तता रहेगी और लगभग उसी समय में गेहूं ख़रीदी का कार्य भी होगा इसलिए अभी से सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। बैठक में मार्कफेड के एमडी आलोक सिंह, डायरेक्टर खाद्य रविंद्र सिंह, भारतीय खाद्य निगम के विशेष गढ़पाले, नागरिक आपूर्ति निगम के एमडी प्रताप नारायण यादव, कलेक्टर इंदौर आशीष सिंह सहित संभाग के अन्य ज़िलों के कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में श्रीमती स्मिता भारद्वाज ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न गोदामों के निरीक्षण के लिए अंतर जिला दल द्वारा जाँच कराए जाने के निर्देश भी दिए।

समूह लोन ओर छोटे बैकों से लिया उधार

घर का सेटलमेंट कराने के नाम पर दो लोगो ने ठगा,6 लाख रूपये की धोखाधड़ी

इंदौर(नप्र)। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने खुद को बैकों के लोन के लिये सेटलमेंट कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले दो एजेंटो के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने बैंक से लोन खत्म कराने के नाम पर उनसे ठगी की। पुलिस ने इस मामले में दोनो आरोपयिों की तलाश शुरू कर दी है।

विजयनगर पुलिस के मुताबिक अनीता सेन निवासी पवन पुरी कॉलोनी की शिकायत पर यशवंत जगताप ओर उसके साथ अलताब उर्फ आलतू खान के खिलाफ धोखाधड़ी ओर ठगी की धाराओं मे केस दर्ज किया गया है। पीड़िता ने बताया कि 600 स्के फीट पर मकान बनाने के लिये उन्होंने 2019 में उन्होंने आईएफएल बैक से 9 लाख 30 हजार रूपये लोन लिया। कुछ किश्तें भरने के बाद अचानक लॉक डाउन लग गया। जिसमें काम रूक गए। बेटे पवन का सैलनू पार्लर भी बंद हो गया। वह किश्ते भरने में असमर्थ हो गए। इसी बीच बेटे की दुकान पर इलाके में रहने वाला मोनू पटेल से आने जाने के दौरान पवन ने मकान पर लोन होने की बात कही। पवन ने बताया कि उन्हें इसका सेटलमेंट करना है। मोनू ने बताया कि उसका एक दोस्त है। जो बैकों से सेटलमेंट का ही काम करता है। इसके बाद जगताप ओर फिर अलताब से बात हुई।

दोनो ने कहां कि वह सेटलमेंट कर देगे उनकी बैक में बात हो गई। इसके लिये पहले 3 लाख 90 हजार रूपये मांगे गए। पवन ने अलग अलग समूह लोन ओर बैंक व दोस्तो से रूपये लेकर मेंदाता रोड़ आईएफएल बैक के बाहर जगताप ओर अलताब को रूपये दे दिए। कुछ दिन बाद उन्होंने कहां कि बैक से सेटलमेंट के रूपये कम पड़े रहे है। बाद में उन्होंने 1 लाख 90 हजार रूपये ओर मांगे। जिस पर पवन ने यह रूपये भी दोनो को जाकर दे दिए।

तहसीदार का नोटिस मिला तो किये मोबाइल उठाना बंद – अनिता ने बताया कि 7 दिसंबर 2023 को तहसीलदार के माध्यम से बैक संबधी नोटिस उनके पास पहुंचा जिसमें मकान पर बैक संबधी कब्जे की बात लिखी गई। बैक में संपर्क किया तो पता चला कि यहां कोई भी किश्ते जमा नही की गई। इसके बाद उन्होंने जगताप ओर अलताब से संपर्क करने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने जबाव नही दिया। इसी बीच जगताप ने कहां कि एक माह में सेटलमेंट हो जाएगा। नोटिस आना बंद हो जाएगें। इसके बाद उनके अलग अलग तारीखों पर तीन ओर नोटिस तामिल हुए। अनीता ओर उनके बेटे पवन ने बैक अफसर ओर तहसीलदार के समक्ष बात रखी। तब बैक ने जगताप ओर अलताब के नाम का कोई भी व्यक्ति उनके संपर्क में नही होन की बात की। मामले में अफसरो को शिकायत की गई। जिसमें बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया।

इंदौर की पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष बीजेपी में शामिल

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई जया तिवारी को सदस्यता

इंदौर (नप्र)। इंदौर की पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष जया तिवारी बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। उन्हें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा ने सदस्यता दिलाई। इससे पहले इंदौर के संजय शुक्ला और विशाल पटेल बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी कुछ और कांग्रेसियों के भी बीजेपी में शामिल होने के संकेत दे चुके हैं। बुधवार को भोपाल के भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा,पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नागेंद्र सिंह चौहान,भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू ने जया तिवारी को भाजपा का दुपट्टा पहनाकर सदस्यता दिलाई। श्रीमती तिवारी इंदौर में पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी है और काफी समय से महिला कांग्रेस में सक्रिय थी अब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। श्रीमती तिवारी ने कहा कि अयोध्या श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण जब कांग्रेस ने ठुकराया तो मुझे बहुत बुरा लगा इसलिए मैने कांग्रेस छोड़ दी है। अब भाजपा में राष्ट्र सेवा के लिए कार्य करूंगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में कई भाजपा महिला कार्यकर्ता मौजूद रही।

विधानसभा निर्वाचन 2024 - व्यय लेखा दलों का प्रशिक्षण 14 मार्च को

इंदौर। लोकसभा निर्वाचन 2024 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने तथा व्यय लेखा संबंधी कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह द्वारा व्यय लेखा अधिकारी, सहायक व्यय प्रेक्षक, निर्वाचन व्यय लेखा दल, SST, FST, VST, VVT के दलों गठन किया गया है। उक्त दलों का प्रशिक्षण 14 मार्च 2024 को दोपहर 02: 30 बजे से लता मंगेशकर सभागृह राजेन्द्र नगर इन्दौर के में रखा गया है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त व्यय लेखा प्रभारियों, समस्त सहायक व्यय प्रेक्षक एवं SST, FST, VVT, VST को अपने दल सहित प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उपस्थित रहने के निर्देश दिए गये हैं।

दैनिक सद्भावना पाती
इंदौर, गुरुवार 14 मार्च, 2024

संपादकीय

चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे से उठे सवाल

अगर किसी महत्वपूर्ण मैच से ठीक पहले ही अम्पायर को बदल दिया जाए तो आपके मन में कोई सवाल खड़ा होगा? अगर खबर आए कि मैच से एक दिन पहले एक अंपायर ने रहस्यमय स्थिति में इस्तीफा दे दिया है तो आप क्या सोचेंगे? अगर पता लगे कि 3 में से 2 नए अंपायरों की नियुक्ति मैच में खेल रही एक टीम का कैप्टन करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अगर यह सब न्यूट्रल यानी निष्पक्ष अम्पायर को नियुक्त करने की सिफारिश के बावजूद हुआ हो तो? आपके मन में पूरे खेल की विश्वसनीयता पर सवाल उठेगा या नहीं? यही सवाल लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ ही दिन पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे से करोड़ों भारतीय नागरिकों के मन में उठ रहे हैं। फिलहाल हम इस्तीफे के कारण और परिस्थिति के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते। बस इतना जरूर जानते हैं कि अरुण गोयल का कार्यकाल 2027 तक का था। अगले साल यानी 2025 में उनके मुख्य चुनाव आयुक्त बनने का नंबर था। ऐसी बड़ी कुर्सी को कोई जल्दी से नहीं छोड़ता। इस्तीफे का कोई व्यक्तिगत कारण हो, ऐसी कोई खबर नहीं है। अगर वास्तव में ऐसा कुछ होता तो सरकार की तरफ से प्रचारित कर दिया जाता। मीडिया में जो खबर चलाई जा रही है, वह यह कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मतभेद के चलते इस्तीफा दिया। इस पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि अगर व्यक्तिगत मतभेद थे तो अरुण गोयल को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार था, उनके वोट का भी उतना ही वजन होता। और अचानक इतना गहरा क्या मतभेद हुआ, जिससे रातों-रात एक संवैधानिक पद से इस्तीफा देने की नौबत आ गई? यूं भी अगर गंभीर मतभेद भी था तो यह कुछ समय की बात थी क्योंकि अगले साल तक तो राजीव कुमार रिटायर हो जाते। अभी तक यह खबर नहीं है कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त से मतभेद था तो किस मुद्दे पर था। बस हम इतना जानते हैं कि दोनों चुनाव आयुक्त पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे, वहां चुनावी तैयारी का जायजा ले रहे थे। उस दौरान कुछ ऐसी बात हुई, जिसके बाद अरुण गोयल ने वहां प्रैस कांफ्रैंस में भाग नहीं लिया। अगले दिन चुनाव आयोग में हुई एक औपचारिक बैठक में हिस्सा लिया लेकिन उसके तुरंत बाद किसी को बताए बिना इस्तीफा दे दिया।

खबर यह भी है कि कुछ अफसरों द्वारा मनाने के कोशिश भी हुई लेकिन वह टस से मस नहीं हुए। इससे ज्यादा खबर न तो है, न ही जल्द मिलने को कोई उम्मीद है। हो सकता है कुछ साल बाद किसी पुस्तक के विमोचन पर इसका खुलासा हो, जैसे जनरल नरवणे ने अब एक किताब में बताया कि सेना ने अग्निवीर योजना का विरोध किया था (उस किताब को अभी रोक लिया गया है)। इसलिए सारा देश कयास लगाने पर मजबूर है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की विशेष दिलचस्पी है। अगला चुनाव जीतने के भाजपा के मंसूबे पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनाव में हुई जबरदस्त हार को पलटने पर टिके हैं। और उसके लिए पुलिस, सुरक्षा बलों, प्रशासन और चुनाव आयोग का सहयोग बहुत जरूरी है। तो क्या भाजपा पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग से कुछ ऐसा चाहती थी, जिसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजी थे लेकिन अरुण गोयल असहज थे? या कि मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं, पूरे देश के स्तर पर था? क्या चुनाव आयुक्त पर कुछ ऐसा करने का दबाव था, जो वह कर नहीं पा रहे थे? क्या उन्होंने अपनी असहमति सरकार में किसी के सामने नहीं रखी होगी? मुख्य चुनाव आयुक्त से असहमति के कारण इस्तीफे की नौबत तभी आती है, अगर कहीं 'ऊपर से' इशारा हो कि चुपचाप से उनकी बात मान लो वरना... !

ऐसा कयास आधारहीन नहीं है। पिछले चुनाव के दौरान भी ऐसी घटना हो चुकी है। उस समय चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा। उन्हें भी मोदी सरकार ने ही चुनाव आयुक्त बनाया था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा द्वारा चुनावी आचार संहिता के घोर उल्लंघन के कुछ मुद्दों पर चुनाव आयोग की अंदरूनी बैठकों में आपत्ति जताई। चुनाव से पहले नमो चैनल लांच करने को आचार संहिता का उल्लंघन बताया। बाकी दो चुनाव आयुक्तों ने उनकी राय को नहीं माना और भाजपा का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसी वक्त सरकार की एजैंसियों ने उनकी पत्नी और बच्चों के विरुद्ध जांच करनी शुरू कर दी। उसके बाद 2020 में अशोक लवासा चुपचाप से चुनाव आयोग से इस्तीफा देकर विदेश चले गए और जांच अपने आप बंद हो गई। सवाल है कि अरुण गोयल ने भी कहीं अशोक लवासा जैसी स्थिति से बचने के लिए तो इस्तीफा नहीं दिया? मतभेद मुख्य चुनाव आयुक्त से नहीं, बल्कि सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता से थे? अभी ये कयास ही हैं। अरुण गोयल खुद दूध के धुले हों, ऐसी बात नहीं है। सच यह है कि उनकी नियुक्ति भी इतने विवादास्पद तरीके से हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट को उनकी नियुक्ति के तरीके पर कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी थी।

सोशल मीडिया से...

पहले की सरकारों ने यहां की विरासत को बचाने की कोशिश ही नहीं की। इसका कारण उनकी तुष्टीकरण की नीति थी। इसी के चलते हमारे देश की महान धरोहर ऐसे ही तबाह होती चली गई। अतिक्रमण, अस्वच्छता और अव्यवस्था ने हमारे देश की महान विरासत को घेर रखा था, जिसे मुक्त कराने का हमारा अभियान जारी है।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

हमने पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए। सवाल यह है कि किस बारे में बात की जानी है... अगर किसी के पास इतनी अधिक संख्या में आतंकवादी ठिकाने हैं... तो वही बातचीत का केंद्र होना चाहिए।''

एस जयशंकर, विदेश मंत्री

हमारी सरकार राज्य में सीएए को लागू नहीं करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक लाभ हासिल करने के प्रयास में लोकसभा चुनाव से पहले सीएए के नियमों को अधिसूचित कर रहे हैं। इसके जरिए वह अपने डूबते जहाज को बचाने की कोशिश में हैं।

एमके स्टालिन, सीएम तमिलनाडु

सीएए कानून वैध है या नहीं, मुझे संदेह है। इसे लेकर केंद्र सरकार की स्पष्टता नहीं है। 2019 में असम में एनआरसी के नाम पर 19 लाख में से 13 लाख बंगाली हिंदू को लिस्ट से हटा दिया गया था। कई लोगों ने आत्महत्या की थी। अगर वे लोग दर्खास्त करेंगे तो क्या उन्हें नागरिकता मिलेगी?

ममता बनर्जी, सीएम प. बंगाल

आज का कार्टून

भाजपा का चुनावी दांव है नागरिकता संशोधन क़ानून

> चुनावों में विपक्षी पार्टियों को अब यह वायदा करना पड़ सकता है कि सत्ता में आने पर वे नागरिकता संशोधन क़ानून में फिर संशोधन करेंगे और इस क़ानून को सेक्यूलर क़ानून बनाएंगे, जिसमें धर्म के आधार पर नागरिकता का प्रावधान खत्म किया जाएगा। विपक्ष के इस वायदे से चुनावों में धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण तेज होगा, जिसका विपक्ष को फायदा होने की बजाए नुकसान ही होगा, क्योंकि 2020 के नागरिकता संशोधन क़ानून के खिलाफ चले हिंसक आन्दोलन के घाव फिर हरे हो जाएंगे। वैसे मोदी सरकार ने क़ानून की नियमावली लागू करके विपक्ष को एकजुट होने का सुअवसर प्रदान कर दिया है। मोदी सरकार चुनावों की घोषणा से पहले अपने बचे हुए काम निपटा देना चाहती है। चुनावों की घोषणा 19 मार्च के बाद कभी भी हो सकती है। 2019 में 10 मार्च को लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई थी, दस मार्च जा चुकी है और चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है।

अजय सेतिया

मोदी सरकार ने अपना वायदा निभाते हुए नागरिकता संशोधन क़ानून के नियम जारी कर दिए हैं। विपक्ष, खासकर तृणमूल कांग्रेस, ऐसा मानकर चल रहे थे कि 2020 के नागरिकता संशोधन क़ानून के खिलाफ हुए मुस्लिम आन्दोलन से डर कर जैसे मोदी सरकार ने पिछले चार साल में सीएए के नियम लागू नहीं किए, वैसे ही चुनावों तक उसे ठंडे बस्ते में डाले रखेगी।

इस क़ानून का मुस्लिमों की ओर से विरोध इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि वे चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर सताए गए हिन्दुओं, सिखों, जैनियों, बोद्धों, पारसियों और ईसाईयों को क़ानून में ढील देकर भारत की नागरिकता दी जा रही है, वैसे ही बांग्लादेश और म्यांमार से आए मुस्लिमों को भी नागरिकता दी जाए। जबकि भारत सरकार की नजर में बांग्लादेश एक मुस्लिम देश है, वहां मुसलमानों को धार्मिक आधार पर सताए जाने का कोई कारण ही नहीं है।

जहां तक म्यांमार का सवाल है, तो वहां बांग्लादेशी मुसलमानों की हिंसक गतिविधियों के खिलाफ वहां के बोद्धों की प्रतिहिंसा के चलते उन्हें वहां से भागना पड़ा है, लेकिन क्योंकि वे मूल रूप से बांग्लादेशी हैं, इसलिए उन्हें वापस बांग्लादेश जाना चाहिए, न कि भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ करनी चाहिए। भारत सरकार का तर्क है कि पडौसी मुस्लिम देशों से आए गैर मुस्लिम वैध पासपोर्ट से भारत में आए, लेकिन वीजा खत्म होने के बाद यहाँ से वापस नहीं गए, जबकि बाग्लादेश और म्यांमार से कोई भी मुस्लिम वैध तरीके से भारत में नहीं आया है।

पश्चिम बंगाल की पूर्ववर्ती कम्युनिस्ट सरकार और मौजूदा तृणमूल कांग्रेस सरकार ने अवैध घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा कर उन्हें चुनाव जीतने का औजार बना रखा है। इसी तरह असम और पूर्वोतर के अन्य सीमान्त राज्यों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने भी अवैध तरीके से उनके वोट बनवा दिए। अब इन दोनों राज्यों की भाजपा विरोधी पार्टियां चाहती हैं कि नागरिकता संशोधन क़ानून में इन घुसपैठियों को भी नागरिकता दी जाए। इन अवैध घुसपैठयों के खिलाफ अस्सी के दशक में बहुत बड़ा आन्दोलन चला था, तबकी राजीव गांधी सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों के साथ किए समझौते में घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने का वायदा भी किया था, लेकिन वह वायदा किसी सरकार ने निभाया नहीं। क्योंकि अवैध घुसपैठिए उनका वोट बैंक बन गए थे।

इसलिए नागरिकता संशोधन क़ानून का विरोध करने वाले मुसलमानों के साथ विपक्षी पार्टियां भी शामिल थीं। मोदी सरकार ने देश भर में हुए हिंसक आन्दोलन के चलते क़ानून के नियम लागू नहीं किए थे। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह शुरू से कह रहे थे कि संसद से पारित क़ानून लागू किया ही जाएगा।

अभी करीब एक महीना पहले से उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया था कि लोकसभा चुनावों से पहले ही नागरिकता संशोधन क़ानून की नियमावली जारी कर दी जाएगी, और उसी के साथ ही क़ानून के दायरे में आने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

पश्चिम बंगाल और असम में तो यह एक बड़ा राजनीतिक विषय है, क्योंकि वहां बड़ी तादाद में बांग्लादेशी हिन्दू रह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें नागरिकता देकर अपने वोट बैंक में तब्दील करना चाहती है। जबकि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस अपने बांग्लादेशी मुस्लिम वोट बैंक को भरमाते रहे हैं कि वे भेदभाव वाला यह क़ानून लागू नहीं होने देंगे, अगर केंद्र सरकार बांग्लादेशी हिन्दू शरणार्थियों को नागरिकता देगी, तो वे उन्हें भी नागरिकता दिलाएंगे।

विपक्षी दलों और मुस्लिमों के विरोध के चलते प्रतिक्रिया में यह क़ानून भारत के हिन्दुओं के लिए भी बड़ा मुद्दा बन गया था। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सार्वजनिक मंचों से मोदी सरकार को चुनौती देती रही थीं कि वह नागरिकता संशोधन क़ानून और नागरिकता रजिस्टर लागू करवा कर दिखाएं।

इस चुनौती को अमित शाह सार्वजनिक मंचों से स्वीकार करते रहे हैं, लेकिन पिछले छह महीनों से संशय बना हुआ था कि सरकार चुनावों से ठीक पहले नागरिकता संशोधन क़ानून को लागू करके रिस्क लेना चाहेगी या नहीं। हालांकि भारत के नागरिकों का इस क़ानून से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन भाजपा समर्थकों ने इस क़ानून को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। इसलिए लोकसभा चुनावों से पहले नियमावली लागू नहीं होती, तो इसे भाजपा सरकार की कमजोरी माना जाता।

चुनावों की घोषणा से करीब दस दिन पहले मोदी सरकार ने नियमावली लागू करके अपने काडर का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, दिल्ली और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में बड़ा दांव खेल दिया हैं। इन सभी राज्यों में जहां बांग्लादेशी और म्यांमारी घुसपैठिए भरे पड़े हैं, वहीं पश्चिम बंगाल और असम में तो विपक्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण वोट बैंक है, तो इन्हीं दोनों देशों से आए हिन्दू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन भाजपा का वोट बैंक हैं, जिन्हें भाजपा ने नागरिकता का तोहफा देकर अपने वोट को और मजबूत किया है।

चुनावों में विपक्षी पार्टियों को अब यह वायदा करना पड़ सकता है कि सत्ता में आने पर वे नागरिकता संशोधन क़ानून में फिर संशोधन करेंगे और इस क़ानून को सेक्यूलर क़ानून बनाएंगे, जिसमें धर्म के आधार पर नागरिकता का प्रावधान खत्म किया जाएगा। विपक्ष के इस वायदे से चुनावों में धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण तेज होगा, जिसका विपक्ष को फायदा होने की बजाए नुकसान ही होगा, क्योंकि 2020 के नागरिकता संशोधन क़ानून के खिलाफ चले हिंसक आन्दोलन के घाव फिर हरे हो जाएंगे।

वैसे मोदी सरकार ने क़ानून की नियमावली लागू करके विपक्ष को एकजुट होने का सुअवसर प्रदान कर दिया है। मोदी सरकार चुनावों की घोषणा से पहले अपने बचे हुए काम निपटा देना चाहती है। चुनावों की घोषणा 19 मार्च के बाद कभी भी हो सकती है। 2019 में 10 मार्च को लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई थी, दस मार्च जा चुकी है और चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है।

अब लोकसभा चुनावों की घोषणा 19-20 मार्च को संभावित है। तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी हो चुकी होगी। हालांकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कांग्रेस के बायकाट करने या अडंगा डालने की प्रबल आशंका है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी 17 मार्च को समाप्त हो जाएगी। राहुल गांधी अपनी यात्रा के माध्यम से और नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों के माध्यम चुनावी माहौल बना ही चुके हैं।

लद्दाख के विशेष दर्जे की मांग कैसे पूरी होगी...

> लोकसभा चुनावों की पूर्वबेला पर प्रधानमंत्री मोदी ने नए कश्मीर के निर्माण का आह्वान किया है। दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह ने लद्दाख के लोगों से मिलकर विशेष दर्जा देने की मांग पर विचार किया है। लोकसभा के आम चुनावों में लद्दाख की एक लोकसभा सीट पर मतदान होगा, लेकिन वहां पर लोकसभा की 2 सीटें बनाने की मांग हो रही है। लोकसभा की सीट बढ़ाने के लिए 2026 में परिसीमन का प्रावधान है लेकिन उसके लिए जनगणना का काम पहले करना होगा, जिसकी साल 2021 से गाड़ी अटकी हुई है।

विराग गुप्ता

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के साथ राज्य का दो हिस्सों में विभाजन के बाद अक्तूबर 2019 में लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश की मान्यता मिली। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 की समाप्ति पर मोहर लगाते हुए जम्मू-कश्मीर की विधानसभा के लिए सितम्बर तक चुनाव कराने के आदेश दिए थे, लेकिन लद्दाख राज्य में विधानसभा के गठन के लिए संसद ने कानून में प्रावधान नहीं किए।

अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद नेतागिरी की वजह से कश्मीर और लद्दाख के लोगों को डर है कि बाहरी लोगों के आने से उनकी नौकरी, जमीन और संस्कृति खतरे में आ सकती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लद्दाख की आबादी दिल्ली की ढाई फीसदी से भी कम है। दूसरी तरफ क्षेत्रफल के लिहाज से यह दिल्ली से 40 गुना बड़ा है। लेकिन लद्दाख के आधिकारिक क्षेत्रफल 1.66 लाख वर्ग कि.मी. में सिर्फ 59146 वर्ग कि.मी. ही भारत के नियन्त्रण में है। शेष इलाके पर पाकिस्तान और चीन का अवैध कब्जा है, जहां की सीमाएं गिलगित, बाल्टिस्तान और अक्साई चिन से मिलती हैं। लद्दाख के पूर्व में तिब्बत पर भी चीन ने अवैध कब्जा किया हुआ है। इसलिए सीमावर्ती लद्दाख में स्वायत्तता के लिए हो रहे बड़े विरोध प्रदर्शनों को गम्भीरता से लेने की जरूरत है। देश में डबल इंजन सरकार की चर्चा जोरों से होती है लेकिन निचले हिस्से तक विकास के लिए पंचायतों यानी तीसरे इंजन का सशक्तीकरण भी जरूरी है। इसके लिए साल 1993 में संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था। जम्मू-कश्मीर में साल 2018 में पंचायतों के चुनाव हुए थे। कानून में बदलाव करके सितम्बर 2018 में पंचायतों को 29 मामलों में अधिकार दिए गए थे। उनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्कूल और आंगनबाड़ी आदि प्रमुख थे। पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल 2023 में खत्म हो गया और उसके बाद नए चुनाव नहीं हुए। केन्द्र सरकार के अनुसार सीटों के पुनर्गठन के बाद पंचायतों का चुनाव होगा। लोकसभा ने जम्मू-कश्मीर में पंचायती राज के बारे में तीन बिलों को मंजूरी दी है लेकिन लद्दाख में विधानसभा के गठन के लिए कोई व्यवस्था नहीं

होने से उलझनें बढ़ रही हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अनुच्छेद 371 लागू करने का सुझाव दिया है।

अनुच्छेद 371 की व्यवस्था : लद्दाख में दो प्रमुख मांगें हैं। पहली, जनता द्वारा चुनी गई सरकार और स्थानीय प्रशासन, जिसके पास अनेक अधिकार हों। दूसरी, भूमि और संस्कृति की रक्षा के साथ सरकारी नौकरी में आरक्षण। दिसम्बर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर मुहर लगाते हुए कहा था कि यह प्रावधान संविधान के अस्थायी और संक्रमणकालीन अध्याय-21 का हिस्सा है। उसी तरह से अनुच्छेद 371 भी 21वें अध्याय का हिस्सा है, जिसमें अस्थायी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 371 की संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से धार्मिक या सामाजिक समुदाय को भौगोलिक क्षेत्र में स्वायत्तता के विशेष अधिकार हासिल होते हैं। अनेक संविधान संशोधनों से अनुच्छेद 371 के दायरे में कई राज्यों को शामिल किया गया, जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आन्ध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक प्रमुख हैं। इसके दायरे में लद्दाख को लाने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत हो सकती है। यह प्रावधान लागू होने पर लद्दाख में स्थानीय संस्कृति के संरक्षण के साथ बाहरी लोगों को सम्पत्ति की बिक्री पर रोक लग सकती है।

छठी अनुसूची का विकल्पः संविधान की छठी अनुसूची में किसी राज्य के जनजातीय इलाकों को विशेष संरक्षण देने का प्रावधान है। इसके लिए लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश के कानून में संसद से बदलाव किए जा सकते हैं। छठी अनुसूची लागू होने पर लद्दाख में स्वायत्त जिला परिषद या स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद की स्थापना हो सकेगी। उस परिषद में चुने हुए सदस्यों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार होंगे। परिषद को ग्रामीण प्रशासन, कृषि, वन, शादी, तलाक, उत्तराधिकार जैसे विषयों पर कानून बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार हासिल होगा। सिविल और क्रिमिनल मामलों के लिए परिषद के तहत स्थानीय अदालतों के गठन के लिए भी राज्यपाल मंजूरी दे सकते हैं। प्रशासन चलाने के लिए टैक्स, भूमि-राजस्व, खनिज में रॉयल्टी और व्यापार में कर वसूली का अधिकार भी परिषद को मिल सकता है। स्थानीय स्तर पर टैक्स वसूली के पैसों से परिषद सड़क, अस्पताल, बाजार और स्कूलों का निर्माण करवा सकेगी। अनुच्छेद 371 और छठी अनुसूची के प्रावधानों में खासा फर्क है। अनुच्छेद 371 अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान है, जबकि छठी अनुसूची के प्रावधान स्थायी प्रकृति के हैं। अनुच्छेद 371 के तहत सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था के संरक्षण पर ज्यादा जोर है। दूसरी ओर छठी अनुसूची के अनुसार विशिष्ट क्षेत्र को मिनी राज्य का दर्जा और अधिकार मिल जाता है, जिसके तहत उन्हें कानून बनाने, टैक्स वसूलने, न्यायालय और विकास कार्य करने के अनेक अधिकार हासिल होते हैं। छठी अनुसूची अनुच्छेद 244 (2) और अनुच्छेद 275 (1) से संचालित है, जिनमें जनजातीय क्षेत्रों के विकास और ग्रांट के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसलिए अनुच्छेद 371 की बजाय छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को ज्यादा अधिकार हासिल होंगे। इसके लिए सरकार को संविधान में संशोधन भी नहीं करना होगा। लेकिन लद्दाख के लिए विशेष व्यवस्था को मंजूरी देने के बाद अन्य राज्यों में भी ऐसी मांग बढने से राष्ट्रीय एकता के लिहाज से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद मुख्यधारा में लाने के बाद भारत के मुकुट लद्दाख में जनापेक्षाओं को पूरा करने के लिए ठोस और संतुलित कदम उठाने की जरूरत है।

दैनिक सद्भावना पाती
इंदौर, गुरुवार 14 मार्च , 2024

संक्षिप्त समाचार

चालू वित्त वर्ष में करीब आठ फीसदी रह सकती है विकास दर, 11 अरब डॉलर पहुंच सकता है चालू खाता घाटा

नई दिल्ली, एजेंसी। उद्योग और सेवा क्षेत्रों की गतिविधियों में तेजी से चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर करीब आठ फीसदी रह सकती है। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने कहा, सांख्यिकी मंत्रालय का अनुमान 7.6 फीसदी है। लेकिन, विकास दर इससे ज्यादा होगी। नागेश्वरन ने मंगलवार को कहा, जब तक चौथी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े उस गति से बहुत कम नहीं हो जाते जो हमने पहली तीन तिमाहियों में देखी है, तो वृद्धि दर 7.6 फीसदी के बजाय 8 फीसदी के करीब होगी। हालांकि, उत्साह के आगे झुके बिना लक्ष्य की ओर सिर झुकाकर काम करने की जरूरत भी है। उन्होंने कहा, एक देश के रूप में हमें महसूस करना चाहिए कि हम लंबी अवधि के लिए काम कर रहे हैं, न कि छोटी अवधि के लिए। चालू वित्त वर्ष के लिए उद्योग और सेवाओं में वृद्धि दिख रही है। देरी व अनियमित मानसून के कारण कृषि क्षेत्र की विकास दर पर असर देखने को मिल सकता है। देश का चालू खाता घाटा 2023-24 की तीसरी तिमाही यानी अक्तूबर-दिसंबर में बढ़कर 11 अरब डॉलर या जीडीपी का 1.2 फीसदी तक पहुंच सकता है।रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने यह अनुमान जताया है।जुलाई-सितंबर तिमाही में चालू खाता घाटा एक फीसदी रहा था, जबकि 2022-23 में दो फीसदी रहा था। एजेंसी का दावा है कि चौथी तिमाही में चालू खाता घाटा कम हो सकता है, क्योंकि वैश्विक आर्थिक गतिविधि में तेजी के शुरुआती संकेत दिख रहे हैं। हमारा निर्यात बेहतर रहेगा।

1.1 अरब डॉलर के लिए आईएमएफ मिशन और पाकिस्तान के बीच होगी चर्चा, 14 से 18 मार्च के बीच बैठक

नई दिल्ली, एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) मिशन तीन अरब डॉलर की स्टैंड-बाय व्यवस्था (एसबीए) की आर्थिक समीक्षा के लिए बुधवार को पाकिस्तान पहुंच सकता है। सूत्रों के मुताबिक, यह बातचीत 14 से 18 मार्च तक होगी। पाकिस्तान के नवनिर्वाचित वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब समझौते और एक नए ऋण कार्यक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बातचीत के लिए सहमत हो गए हैं। एआरवाई न्यूज के अनुसार, इस्लामाबाद एसबीए कार्यक्रम के तहत 1.1 बिलियन अमरीकी डालर की अंतिम किश्त के बारे में अंतरराष्ट्रीय ऋणदाता के साथ बातचीत करेगा। इसके अलावा, पाकिस्तान ने दूसरी समीक्षा के लिए आईएमएफ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पहले ही हासिल कर लिया है, सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। बातचीत के दौरान, पाकिस्तान एक साथ 36 महीने की विस्तारित निधि सुविधा (ईएफएफ) के तहत एक नए सौदे का अनुरोध भी करेगा। सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान 6-8 अरब डॉलर के नए ऋण के लिए आईएमएफ से अनुरोध कर सकता है।

कॉलेज पर दो लाख का जुर्माना, विश्वविद्यालय का आदेश मिलने के बाद कॉलेज में हड़कंप

इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने परिणाम घोषित होने के बाद विद्यार्थियों के आंतरिक परीक्षा के अंक भेजने वाले कालेज पर कार्रवाई की है। विश्वविद्यालय ने कालेज पर जुर्माना लगाने का आदेश निकाला है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के हिसाब से दो हजार रुपये जमा करवाना है। मंगलवार को कालेज का स्टाफ जुर्माने की राशि कम करवाने की गुहार लगाने लगा। वैसे अधिकारियों ने जुर्माना की राशि में बदलाव करने से साफ मना कर दिया है, जबकि प्रबंधन के मुताबिक मुख्य परीक्षा शुरू होने से पहले ही अंक भेजे गए थे। फिलहाल इस संबंध में विश्वविद्यालय में किसी भी तरह का कोई प्रमाण नहीं मिला है। दरअसल, विश्वविद्यालय ने एमबीए दूसरे और चौथे सेमेस्टर का परिणाम दस दिन पहले घोषित किया, मगर शिवकुमार सिंह कालेज ने प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक मार्च में दिए। इसके चलते विश्वविद्यालय ने कालेज से पढ़ने वाले 100 छात्र-छात्राओं के परिणाम रोक दिया। लापरवाही बरतने वाले कालेज के खिलाफ विश्वविद्यालय ने कार्रवाई की है। प्रत्येक विद्यार्थी के हिसाब से दो-दो हजार रुपये जमा करने के निर्देश दिए। विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से कालेज को दो लाख रुपये जमा करना है। विश्वविद्यालय का आदेश मिलने के बाद कालेज में हड़कंप मचा गया। राशि कम करवाने के लिए कालेज का स्टाफ तीन दिन से अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। परीक्षा नियंत्रक डा. अशेष तिवारी का कहना है कि कालेज को जुर्माने की राशि भरने के लिए आदेश दिया हैं, मगर प्रबंधन के मुताबिक अंक पहले ही भेजे हैं। कालेज को अंक दिए जाने के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कालेज के डायरेक्टर शरद सिसोदिया का कहना है कि कुछ और कालेज ने अंक देरी से भेजे थे। उन्हें विश्वविद्यालय ने अनुमति दे दी है। वैसे विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर राशि कम करने पर जोर दिया है।

विद्यार्थियों से न वसूली राशि

राशि कम करवाने पहुंचे कालेज के स्टाफ को अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जुर्माने की राशि विद्यार्थियों से न वसूली जाए, बल्कि परीक्षा समय पर नहीं करवाने और अंक भेजने में कालेज की लापरवाही सामने आई है। मौखिक आदेश में अधिकारियों ने स्टाफ को राशि कालेज द्वारा जमा करने पर जोर दिया है। मुख्य और आंतरिक परीक्षा के अंकों के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन होता है। नियमानुसार मुख्य परीक्षा शुरू होने के पहले कालेजों को आंतरिक व प्रैक्टिकल परीक्षा करवाकर अंक भेजने होते हैं। इसके लिए पहले कालेजों को एमपी आनलाइन पर अंक अपलोड करने होते हैं। आंतरिक परीक्षा के अंकों की हार्ड कापी भी विश्वविद्यालय में भिजवाई जाती है, मगर कालेज प्रक्रिया का पालन ठीक से नहीं करते हैं। अधिकांश समय परीक्षा होने के बाद कालेजों से अंक प्राप्त होते हैं।

डीएवीवी - बीएड सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट पर आपत्ति

विद्यार्थियों का आरोप– कापियों में जवाब ठीक से नहीं जांचे

इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की छात्र ने मूल्यांकन पर सवाल खड़े कर दिए। छात्राओं का कहना था कि कापियां देखने पर पता चला कि शिक्षकों ने ठीक से जवाब नहीं जांचे हैं। यहां तक कि सही जवाब को गलत कर आधा नंबर दिया है। कम नंबर दिए जाने से अधिकांश छात्र-छात्राएं फेल हो गए हैं। इसकी वजह से छात्रवृत्ति रुक गई है। अब कालेज फीस जमा करने का दबाव बना रहा है। अधिकांश विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। ऐसे में फीस कहां से भरेंगे। मामले में अधिकारियों ने विद्यार्थियों को समझाया और महीनेभर के भीतर विशेषज्ञों से कापियां जंचवाने का आश्वासन दिया है।

छात्र सुनवाई में खंडवा स्थित पूनमचंद गुप्ता वोकेशनल कालेज की 30 छात्राएं पहुंचीं। उन्होंने बीएड सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट पर आपत्ति जताई। छात्राओं का कहना था कि अधिकांश विद्यार्थी एक-एक विषय में फेल हुए हैं। इसमें अधिगम और शिक्षण, इतिहास शिक्षण, गणित शिक्षण और हिन्दी शिक्षण विषय शामिल हैं। सभी विद्यार्थियों को पास होने में तीन से चार नंबर कम है। रिव्यू में कापियां देखने के बाद पता चला कि मूल्यांकन अच्छे से नहीं किया गया है। इसके चलते विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो रहा है। अधिकांश छात्र-छात्राएं संविदा शिक्षक वर्ग-3 के लिए चयनित हो चुके हैं। अब एटीकेटी आने से प्रक्रिया से बाहर होने की नौबत आ चुकी है।छात्राओं को समझाते हुए परीक्षा नियंत्रक डा. अशेष तिवारी ने कहा कि बीएड में आठ हजार विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इसमें साढ़े तीन हजार छात्र-छात्राओं ने रिव्यू के लिए आवेदन किया है। अब इनकी कापियां जांचने में कम से कम एक महीना लगेगा। कापियां विषय विशेषज्ञों से जंचवाएंगे। परीक्षा नियंत्रक डा. तिवारी ने कहा कि छात्र सुनवाई में 50 प्रकरण आए है, जिसमें 40 सिर्फ बीएड सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट से जुड़े हुए थे।

Indian beer startups growing, launching new products after surge in funding

Amid the rise in funding, beer startups in India are expanding and launching new products to cater to the market, which is seeing growing disposable income and decreasing societal stigma around alcohol. The Indian beer market reached Rs 383.6 billion in 2022 and is expected to reach Rs 622.4 billion by 2028, exhibiting a compound annual growth rate (CAGR) of 8.1 per cent during 2023-2028, according to IMARC Group.

Homegrown beer brand Proost Beer, a subsidiary of Grano69 Beverages, secured Rs 27.5 crore through a mix of equity and debt funding last year. Presently operating in Delhi, Punjab, Uttar Pradesh, and Kerala, Proost plans expansion into five new markets. The company also aims to diversify its product portfolio, focusing on 'mass premium affordable' beers in the strong beer category.

Proost attributes the growth in the beer market to rising per capita beer consumption, increased disposable income, and diminishing societal stigma around alcohol. "There's a notable increase in young consumers who are open to enjoying quality beer while socialising with peers. Moreover, the expansion of the middle class, coupled with rising disposable incomes, has led to increased spending on alcoholic beverages like beer. Obviously, with huge potential of growth when compared to other nation's per capita beer consumption, there is a substantial investment opportunity," said VP Sharma, managing director, Grano69 Beverages.

B9 Beverages, the maker of Bira 91 beer, has secured $200 million in funding so far. Most recently it raised $25 million from Tiger Pacific Capital, an Asia-focused fund based in New York and Hong Kong. On the back of favourable trends, Bira 91 anticipates substantial growth, particularly with younger consumers favouring lower alcohol by volume (ABV), taste-centric drinking, and increased participation including women. "We launch one new product every week at our taprooms and have a robust new product pipeline. We launched several new products last year, including Hill Station Ciders, Grizly Hard Seltzers, and Rise. This year, we have an exciting lineup aswell for the summer," said Ankur Jain, founder and CEO, Bira 91.

Consumer perception - Reybier Alo Bev, India's first woman-led brewery in Goa, said that consumer priorities of affordability and 'value for money' thinking are driving its growth. Reybier aims to re-launch the 'Indian heritage' beers to bridge the gap between generations and genders. "We have two commercial beer brands – Royal C'zar and Mr.Bob which are available in Goa. As a plan of expansion, we are soon launching these products to other domestic and international markets," said Rasagna Rao Dharmana, founder, Reybier Alco Bev. Mount Everest Breweries Ltd (MEBL), a subsidiary of Associated Alcohols & Breweries Ltd, said the Indian beer industry is experiencing substantial growth in investments. It is driven by factors like rising disposable income, changing demographics, and consumer lifestyle. "These converging factors have led to an increase in investments in the industry since brands are trying to capitalise on the increasing consumer base," said Vedant Kedia, Chief Growth Officer, MEBL. Financing platform GetVantage said the Indian beer market, reaching Rs 414.7 billion in 2023 and projected to hit Rs 781.2 billion by 2032, presents a lucrative opportunity for entrepreneurs and both local and foreign beer brands. With a CAGR of 7.1 per cent from 2024 to 2032, the market's expansion is set to continue, providing enough space for innovation and contribution from homegrown brands. Since 2020, GetVantage has invested in alcoholic beverage and beer brands like Grano69, NAO Spirits, and Moonshine, fostering their expansion plans. The company aims to channelise over $5 million of funds into this sector within the next 12-18 months. "With more people residing in cities, the demand for beer and related alcoholic beverages is rising. The growing societal acceptance of beer among both men and women is reshaping the landscape. Furthermore, the availability of beer in supermarkets is becoming common. With the expansion of retail chains, this market segment is gaining strength," said Karun Arya, Chief Growth Officer, GetVantage.

Regulatory hurdles - Talking about the regulatory challenges, Proost points to the complex Indian landscape with varying state excise policies impacting small beer enterprises. "However, there's a positive trend towards improved ease of doing business, streamlined registration processes, and smoother routes to market entry. The government is demonstrating a willingness to address the industry concerns, while further progress still needs to be made on regulatory reforms," Sharma of Proost said. Bira 91 highlights regulatory challenges like exorbitant beer taxes and outdated state regulations hampering the growth of the segment. "On a per serving basis, taxes are nearly ten times more than whiskey and spirits in several states, making beer one of the most expensive beverages for consumers. Additionally, in countries like Vietnam, Japan or the US, the number of shops and bars that can sell beer is in the millions, whereas, in a country like India, it is less than 100,000," said Jain from Bira 91. To Bengaluru-based World of Brands (WoB), despite favourable macro trends and consumer preferences for beer, inadequate state support hinders growth. High beer taxation and limited 'beer-only licenses' impede market access and distribution, requiring industry efforts to advocate for policy changes. "Taxation on beer is still too high in comparison with spirits which makes beer an expensive product. Besides issues on taxation, preferences in distribution and availability of beer through 'beer only licenses' are limited to few states like Maharashtra and UP that have benefited them. Beer manufacturers have largely failed in providing long-term representations to the state governments, and an argument to get the state governments to provide more favourable policies on beer over spirits," said Gurpreet Singh, co-founder and director, WoB. Rs 781.2 bn is the projected size of Indian beer market by 2032 7.1% is the anticipated growth rate (CAGR) of the beer market between 2024 and 2032

शिक्षकों को मिला एक माह का ग्रीष्मकालीन अवकाश, विद्यार्थियों को 45 दिन की गर्मियों की छुट्टी

इंदौर । हाल ही में शिक्षा विभाग में नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शिक्षकों और विद्यार्थियों को मिलने वाले अवकाश संबंधित निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत इस बार शिक्षकों 30 दिन और विद्यार्थियों को 45 दिन की गर्मियों की छुट्टी मिलेगी। इसमें दशहरा पर 3, दिपावली पर 6 और शीतकालीन पर 5 दिन का अवकाश मिलेगा। आदेश जारी होते ही शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया है।शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश परमार ने बताया कि शिक्षकों और क्लास रूम टीचिंग में लगे अन्य कैडर को 2008 से वार्षिक अर्जित अवकाश, अवकाश लेखा में दर्ज करना बंद कर दिया गया है। शिक्षकों को अब सिर्फ अवकाश के समय काम करने पर अर्जित अवकाश मिलते हैं। वह भी सिर्फ विभाग के आयुक्त और कलेक्टर के आदेश पर काम करने पर।नए शिक्षण सत्र में शिक्षकों को कुल 44 दिवस अवकाश मिलना है। इसके उलट प्रदेश में 2021 से 5 कार्य दिवस सिस्टम लागू है, इस प्रकार प्रदेश के कार्यालयों में कार्यरत संवर्ग को 52 से 54 शनिवार का अवकाश मिलता है, और वे विश्राम अवकाश कैडर में शामिल नहीं हैं, इस लिए उन्हें 30 दिवस का वार्षिक अर्जित अवकाश, अवकाश लेखा में दर्ज होता है। वर्तमान स्थिति में प्रदेश में शैक्षणिक कैडर और गैर शैक्षणिक कैडर के अवकाश की संख्या समान है, लेकिन अर्जित अवकाश प्रदान करने में शासन द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। हम लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त को ज्ञापन देकर मांग करेंगे कि शिक्षकों 60 दिन के अवकाश दिए जाए। इस संबंध में अन्य शिक्षक संगठनों को भी एकजुट किया जा रहा है।

अमेरिका होने वाला है दिवालिया !, एलन मस्क ने कम खर्च करने की दी नसीहत

नई दिल्ली, एजेंसी। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका पर कंगाली का खतरा मंडरा रहा है। यह हम नहीं टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का कहना है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यहां के लोगों को कम खर्चा करने की नसीहत दी है।

दरअसल, एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया गया था कि कुछ समय में अमेरिकी करदाताओं के 100 प्रतिशत पैसे का उपयोग राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। इसका जवाब देते हुए एलन मस्क ने कहा, अमेरिका जल्द दिवालिया हो सकता है। यहां के लोगों को खर्चे में कमी लानी चाहिए नहीं तो यह जल्द ही कंगाल हो जाएगा।

एलन मस्क इस पोस्ट से हुए सहमत

एक यूजर ने पोस्ट में कहा कि अगले कुछ सालों के लिए यह संख्या देखना अच्छा है। व्यक्तिगत आयकर सरकार के राजस्व का लगभग आधा है। फरवरी की बात करें तो अमेरिकी सरकार ने व्यक्तिगत आयकर से 120 अरब डॉलर जुटाए। राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उन्हें फरवरी में 76 अरब डॉलर खर्च करना पड़ा। हम उस दिन से बहुत दूर नहीं हैं जब ऋण पर ब्याज के लिए भुगतान करने के लिए 100 फीसदी व्यक्तिगत आयकर की आवश्यकता होगी।

क्या अमेरिकी मंदी की संभावना है?

अमेरिका के अरबपति बैंकर जेमी डिमोन का कहना है कि अमेरिका में मंदी की संभावना ज्यादा दूर नहीं बै। वहीं, जेपी मॉर्गन चेज के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने कहा, मुझे लगता है कि अगले एक या दो साल में सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना आधी है। सबसे खराब स्थिति मुद्रास्फीतिजनित मंदी होगी। जेमी डिमोन ने ब्याज दरों को कम किया जाना चाहिए या नहीं, इस पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण आर्थिक हालात बिगड़ गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में बेरोजगारी इस समय बहुत कम है, मजदूरी बढ़ती जा रही है। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने कहा, केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को कम करने के करीब पहुंच रहा है। हम इस बात को लेकर और अधिक आश्वस्त होने की प्रतिक्षा कर रहे हैं कि मुद्रास्फीति दो फीसदी पर लगातार बढ़ रही है। जब हमें इस बात का विश्वास हो जाएगा कि हम इससे दूर नहीं हैं, तब प्रतिबंध के स्तर को वापस शुरू करना उचित होगा।

मालिकाना हक जालान कलरॉक को सौंपने पर एनसीएलएटी ने बरकरार रखा फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) ने जेट एयरवेज के मालिकाना हक मामले में फैसला बरकरार रखा है। स्वामित्व जालान कलरॉक कंसोर्टियम को हस्तांतरित किया जाएगा। एनसीएलएटी ने यह भी निर्देश दिया है कि ऋणदाता जेट एयरवेज के शेयर एसआरए (जालान कलरॉक) को जारी कर कंपनी को मालिकाना हक 30 दिनों के भीतर सौंप देंगे। दिवाला अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने साफ किया कि जेट एयरवेज की समाधान योजना बरकरार रहेगी। एनसीएलएटी पीठ ने जेट एयरवेज की निगरानी समिति को 90 दिनों के भीतर स्वामित्व हस्तांतरण पूरा करने का निर्देश दिया है।

इससे पहले ऋणदाताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) को इस मुद्दे पर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। एनसीएलएटी ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं से बनी प्रबंध समिति को सफल समाधान आवेदक (एसआरए) बनाया। इस मामले में जालान कलरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) एसआरए है। एनसीएलएटी ने प्रस्तावित अचल संपत्तियों पर 30 दिनों के भीतर सिक्योरिटी तैयार करने का निर्देश भी दिया।

150 करोड़ रुपये समायोजित करने का निर्देश भी दिया

एनसीएलएटी ने जेट एयरवेज के ऋणदाताओं को कंसोर्टियम की तरफ से भुगतान किए गए 150 करोड़ रुपये को समायोजित करने का भी निर्देश दिया। गौरतलब है कि जेट एयरवेज के ऋणदाता और सफल बोली लगाने वाले जालान कलरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) के बीच एक साल से अधिक समय से कानूनी लड़ाई हो रही है। कंपनी ने बंद पड़ी विमानन कंपनी के प्रबंधन के हस्तांतरण को लेकर मुकदमा दायर किया है।

एनसीएलएटी ने कहा कि हैंडओवर की तारीख से 30 दिनों के भीतर, जालान कलरॉक और ऋणदाताओं को स्वीकृत समाधान योजना के अनुसार लेनदारों को सभी भुगतान पूरे करने होंगे। मालिकाना हक एसआरए को सौंपने के बाद, जेट एयरवेज नियामक अनुमोदन के अधीन व्यवसाय और परिचालन शुरू कर सकता है। इस घटनाक्रम पर जेट एयरवेज ने कहा, एनसीएलएटी ने बिना किसी बदलाव के मूल रूप से स्वीकृत समाधान योजना के कार्यान्वयन की बात कही है। प्राधिकरण ने ऋणदाताओं को विशिष्ट और तत्काल कार्यान्वयन के निर्देश भी दिए हैं।

100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश ; 350 करोड़ की वित्तीय प्रतिबद्धता पूरी

नई दिल्ली, एजेंसी। जालान कलरॉक कंसॉर्टियम (जेकेसी) ने अदालत की तरफ से अनुमोदित समाधान योजना के मुताबिक 350 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता को पूरा कर लिया है। एनसीएलएटी के समक्ष जेट एयरवेज ने बताया था कि प्रस्तावित प्रमोटरों - जालान-कलरॉक कंसोर्टियम ने 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश पूरा कर लिया है। एयरलाइन ने यह भी कहा था कि वह 2024 से परिचालन फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है। ऋणदाता के साथ विवाद के बीच कंपनी दिवालिया हो गई और 2021 में छ्यष्ट ने जेट एयरवेज का मालिकाना हक पाने के लिए बोली लगाई। अप्रैल 2019 से ही जेट एयरवेज की विमानन सेवाएं ठप हैं।

कक्षा 10वीं के बाद सिविल सर्विस की करना चाहते हैं तैयारी, इस स्ट्रीम से करें आगे की पढ़ाई

10वीं पास करने के बाद अक्सर कैंडिडेट आगे की पढ़ाई किस स्ट्रीम से करें इसके लिए परेशान रहते हैं। कई बार छात्र दसवीं और बारहवीं करने के बाद सिविल सर्विस की तैयारी करने का सोचते हैं ताकि वह अपने करियर को बेहतर बना सके। ऐसे में 10वीं और 12वीं करने के बाद सही स्ट्रीम का चुनाव करना बेहद जरूरी हो जाता है। हालांकि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम की आवश्यकता नहीं होती है।

अगर बात करें मुख्य रूप से सिविल सर्विस तैयारी की आप किसी भी स्ट्रीम को चुनकर भविष्य में आईएएस, आईपीएस अधिकारी बन सकते हैं। लेकिन कुछ स्ट्रीम के सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसे पढ़कर भविष्य के करियर को मजबूत कर सकते हैं। इस लेख में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अगर केवल आईएएस और आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी स्ट्रीम बेस्ट साबित हो सकती हैं।

साइंस स्ट्रीम को करें सेलेक्ट

अगर आप फॉरेंसिक साइंस, क्रिमिनोलॉजी जैसे विषयों को पढ़ने और समझने और साइबर सिक्योरिटी जैसे पुलिसिंग के कुछ टेक्निकल फील्ड में स्पेशलाइजेशन हासिल करने की इच्छा रखते हैं, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथेमेटिक्स जैसे विषयों का चयन कर सकते हैं।

आर्ट्स स्ट्रीम का करें चयन

इस स्ट्रीम में छात्रों को इतिहास, पॉलिटिकल साइंस,साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी जैसे विषयों को पढ़ने का अवसर मिलता है। ये सारे विषय सामाजिक मुद्दों, शासन और ह्यूमन नेचर की समझ प्रदान करते हैं। अगर आप कानून प्रवर्तन के फील्ड में काम आ सकता है।

कॉमर्स स्ट्रीम को करें सेलेक्ट

कॉमर्स स्ट्रीम के अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स जैसे विषयों की मदद से फाइनेंस और बिजनेस पर फोकस कर सकते हैं। फाइनेंस से जुड़े क्राइम से निपटने या पुलिस बजट को मैनेज करने में ये विषय आपकी मदद कर सकता है।

कौन सी स्ट्रीम हो सकती है बेस्ट

किसी भी स्ट्रीम को सेलेक्ट करने के लिए छात्र के रूचि और पर्सनल च्वाइस पर डिपेंड करता है। सिविल सर्विस अधिकारी कई एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं। ऐसे में आपको उस विषय को चुनना चाहिए जिसे पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता है। अगर आप आर्ट स्ट्रीम से ग्रेजुएशन या पीजी करते हैं तो आपको आगे चलकर इन विषयों को समझना बेहद ही आसान होता है।

प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स में बनाएं अपना कॅरियर

ऑर्थोटिस्ट और प्रोस्थेटिस्ट ऐसे रोगियों को दूसरों पर निर्भर हुए बिना अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए स्थिरता और गतिशीलता हासिल करने में मदद करते हैं। कोई भी इस ऑर्थोटिस्ट या प्रोस्थेटिस्ट कॅरियर का विकल्प चुन सकता है।

ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवर होते हैं जो ऑर्थोटिक और प्रोस्थेटिक उपकरणों की योजना बनाते हैं, विकसित करते हैं, फिट करते हैं और संशोधित करते हैं। इन उपकरणों में ऑर्थोस ब्रेसिज, जैसे कृत्रिम हाथ और पैर शामिल हैं। ऑर्थोटिस्ट और प्रोस्थेटिस्ट विकलांग रोगियों को सहायता प्रदान करते हैं। वे उन्हें कृत्रिम अंगों (प्रोस्थेटिक्स) से जोड़ते हैं और उन्हें स्थिरता हासिल करने में मदद करते हैं। कई बार दुर्घटना में लोगों के हाथ-पैर भी टूट जाते हैं। ऑर्थोटिस्ट और प्रोस्थेटिस्ट उनके जीवन में सहायक उपकरणों को ठीक करने और गतिशीलता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे हादसों का शिकार हुए इंसान अक्सर आजीवन अपंगता का शिकार हो जाते हैं। ऑर्थोटिस्ट और प्रोस्थेटिस्ट उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि वे मूल अंग को वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन वे कृत्रिम अंगों जैसे ऑर्थोटिक ब्रेसिज या ऑर्थोस के साथ उन्हें फिट करके उन्हें स्थिरता प्रदान कर सकते हैं।

प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स कॅरियर के रूप में ऑर्थोटिस्ट और प्रोस्थेटिस्ट का कॅरियर सभी के लिए उपयुक्त है चाहे वह लड़का हो या लड़की। विकलांगता से पीड़ित लोगों को अक्सर दूसरों पर आजीवन निर्भरता रहना पड़ता है। ऑर्थोटिस्ट और प्रोस्थेटिस्ट ऐसे रोगियों को दूसरों पर निर्भर हुए बिना अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए स्थिरता और गतिशीलता हासिल करने में मदद करते हैं। कोई भी इस ऑर्थोटिस्ट या प्रोस्थेटिस्ट कॅरियर का विकल्प चुन सकता है।

प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स में स्नातक उन छात्रों के लिए एक करियर विकल्प है जो फार्माकोलॉजी, विच्छेदन सर्जरी और यहां तक कि ग्राफिकल संचार जैसे विषयों का अध्ययन करना चाहते हैं ताकि लगभग हर डोमेन में रोगियों की मदद की जा सके। इस कोर्स को करने पर छात्रों को किसी भी प्रोस्थेटिक या ऑर्थोटिक बीमारियों वाले रोगियों के इलाज के लिए एक पेशेवर दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम बनाया जाता है।

प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक्स में स्नातक (बीपीओ) पाठ्यक्रम को देश में हो रही चिकित्सा प्रगति के अनुसार डिजाइन किया गया है। यह छात्रों को न्यूरोमस्कुलर और लोकोमोटर विकारों के पुनर्वास उपचार का विस्तृत अध्ययन प्रदान करता है। इतना ही नहीं, यह पाठ्यक्रम छात्रों को शारीरिक कल्याण के क्षेत्र में सक्षमता बनाने में भी मदद करता है।

प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक्स में स्नातक 4 साल का पूर्णकालिक स्नातक पाठ्यक्रम है जिसे तीन महीने प्रोस्थेटिक्स में और तीन महीने ऑर्थोटिक्स के साथ कुल छह महीने के अनिवार्य प्रशिक्षण के साथ पूरा किया जाता है।

पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले कुछ विशेष विषय इस प्रकार हैं-

- जैवयांत्रिकी
- प्रोस्थेटिक साइंस
- ऑर्थोटिक साइंस
- मोबिलिटी एंड रिहैबीलीटेशन एड्स
- विच्छेदन सर्जरी और इमेजिंग विज्ञान
- सहायक तकनीक
- औषध
- ग्राफिकल संचार
- हड्डी रोग

सभी ऑर्थोटिस्ट और प्रोस्थेटिस्ट को ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स में मास्टर डिग्री पूरी करनी चाहिए। मास्टर प्रोग्राम को पूरा होने में आमतौर पर 2 साल लगते हैं। इन कार्यक्रमों में ऊपरी और निचले छोरों के ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स, स्पाइनल ऑर्थोटिक्स और प्लास्टिक निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री शामिल होती हैं। इसके अलावा, ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स कार्यक्रमों में एक नैदानिक घटक होता है जिसमें छात्र एक आर्थोपेडिस्ट या प्रोस्थेटिस्ट के निर्देशन में काम करता है।

पात्रता

- कक्षा 12 वीं की बोर्ड परीक्षाओं में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषयों में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करें
- कॉलेजों की उच्च रैंकिंग कट-ऑफ को क्लियर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में अच्छा रैंक प्राप्त करें
- पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं को पास करें

शीर्ष संस्थान

- अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान
- राष्ट्रीय लोकोमोटर विकलांग संस्थान, कोलकाता
- क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, तमिलनाडु
- अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज (एयूएस)
- आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी
- चक्रधर पुनर्वास विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
- ईश्वर प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स संस्थान, चेन्नई

प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स के काम

ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स आमतौर पर निम्नलिखित कार्य करते हैं:

- मरीजों की जरूरतों को निर्धारित करने के लिए उनका मूल्यांकन और साक्षात्कार
- रोगी के शरीर के उस हिस्से का माप या छाप लें जहाँ ब्रेस या कृत्रिम अंग लगाया जाएगा
- चिकित्सकों के नुस्खे के आधार पर आर्थोपेडिक और कृत्रिम उपकरणों का डिजाइन और निर्माण करना
- ऑर्थोटिक या प्रोस्थेटिक डिवाइस के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का चयन करना
- रोगियों को उनके उपकरणों का उपयोग करने और उनकी देखभाल करने का निर्देश देना
- प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक उपकरणों को समायोजित, मरम्मत या या उन्हें बदलना

रेगुलर डिग्री के साथ हासिल करें पार्ट टाइम स्किल

कॉलेज में क्लासेज होती हैं दोपहर तक, उसके बाद क्या करें! पर अब आप दोपहर बाद के खाली समय को लेकर परेशान न हों। दिल्ली विश्वविद्यालय के कैम्पस ऑफ ओपन लर्निंग में तरह-तरह के शॉर्ट टर्म कोर्स हैं, जो आपके दोपहर बाद के टाइम को भी सार्थक करेंगे और आपकी जानकारी में भी इजाफा करेंगे।

इन कोर्सों में कुछ बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं तो कुछ पर्सनेलिटी डेवलपमेंट से। ये कोर्स आमतौर तीन से छह माह तक की अवधि के हैं। इन कोर्सों को रेगुलर कोर्स की पढ़ाई करने के साथ-साथ किया जा सकता है।

कोर्स के रंग

केशवपुरम स्थित सेंटर में विश्वविद्यालय ने विभिन्न उद्योगों की मदद से शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू किए हैं। फिलहाल पांच कोर्सेज में दाखिले की प्रक्रिया जारी है। कोर्स हैं- टेलीकॉम, इंश्योरेंस, सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हॉस्पिटेलिटी और सॉफ्ट स्किल।

टेलीकॉम - टेलीकॉम का कोर्स भारती ग्रुप के सेंटम लर्निंग की मदद से चलाया जा रहा है। छह माह के इस कोर्स में दो माह की इंटर्नशिप है। कोर्स में कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर सर्विस और टीम वर्क जैसी चीजें शामिल हैं।

इंश्योरेंस - इंश्योरेंस का कोर्स मेटलाइफ के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें जीवन बीमा और वित्तीय मामलों की जानकारी दी जाती है। विभिन्न तरह के प्रोडक्ट्स और उनके इस्तेमाल के बारे में बताया जाता है। यह कोर्स तीन माह का है, जिसमें एक माह इंटर्नशिप है। इसकी फीस दस हजार रखी गई है।

सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट- सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट विशेष तौर पर स्नातक पास या स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए है। इसमें दाखिला प्रवेश परीक्षा के जरिए होता है। कोर्स में दाखिला पाते ही छात्र को नियुक्ति पत्र भी दिया जाता है, ताकि कोर्स पूरा होते ही छात्र कंपनी के साथ काम कर सके। यह कोर्स बैंक और फाइनेंस सेक्टर में काम के लिहाज से तैयार किया गया है। सीटें 25 हैं और फीस 18 हजार है। कोर्स की अवधि साढ़े तीन माह है। यह हीरो माइंड माइन कंपनी के सहयोग से चल रहा है। इसमें बैंक की जानकारी, बिजनेस कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन और सेलिंग स्किल की जानकारी दी जाएगी।

सॉफ्ट स्किल - सॉफ्ट स्किल में अंग्रेजी कम्युनिकेशन, कॉरपोरेट एप्टीट्यूड, साक्षात्कार का सामना करने के हुनर सिखाए जाते हैं। हॉस्पिटेलिटी का कोर्स होटल उद्योग और अन्य सर्विस सेक्टर में कुशल कर्मचारी तैयार करने को लेकर तैयार किया गया है। सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट को छोड़ कर अन्य सभी कोर्सेज में प्रवेश के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

इन कोर्सों में दाखिला पाने वाले छात्रों को पढ़ाई के दौरान ऑन हैंड ट्रेनिंग भी दी जाती है। संस्थान में आधुनिक लैब भी तैयार की गई है। कक्षाएं आमतौर पर सप्ताह में तीन दिन दो-दो घंटे चलेंगी। कोर्स पूरा होने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय और संबंधित संस्थान संयुक्त रूप से सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। ये कोर्स छात्रों की सहूलियत के मुताबिक चलाए जाते हैं। अगर किसी को सुबह की पाली में क्लास करने में परेशानी है तो वह दूसरी पाली यानी दोपहर बाद भी क्लास कर सकता है।

सीखें कहने की कला

अपनी बात कहने से पहले दूसरों की बात गौर से सुनें-गुनें और उनकी उम्मीदों-अपेक्षाओं को समझें, ताकि जब आपके कहने की बारी आए, तो दूसरे भी आपकी बातों को ध्यान से सुनें और प्रभावित हों। जॉब सर्च, इंटरव्यू या नौकरी के दौरान अपनी बात से दूसरों को मुरीद बनाने की कम्यूनिकेशन स्किल के टिप्स दे रहे हैं मोटिवेटर।

अच्छे वक्ता वे होते हैं, जो बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। आज स्थिति यह है कि आप अपनी बात को कितने प्रभावशाली ढंग से रखते हैं, उसी पर आपको करियर या जीवन के किसी भी क्षेत्र में मिलने वाली कामयाबी निर्भर करती है। जरा सोचिए, आप किसी मंच पर अपनी बात रख रहे हैं, तो लोग उसे क्यों सुनना चाहेंगे? अगर आप वहां उपस्थित लोगों की मन:स्थिति, उनकी रुचियों, अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित विषय को जोड़ेंगे, तभी लोग उससे प्रभावित होंगे। आप चाहे जितनी हायर स्टडी कर लें या तकनीकी ज्ञान हासिल कर लें, जब तक उसके बारे में लोगों को अच्छी तरह बताने की कला में पक्के नहीं हो जाते, तब तक लोग आपके ज्ञान से कतई प्रभावित नहीं हो सकते। इसलिए जितना जरूरी ज्ञान प्राप्त करना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी अपनी कम्यूनिकेशन स्किल विकसित करना है। अगर आप एक बार कहने की कला में पारंगत हो गए, तो चाहे पब्लिक स्पीकिंग हो या फिर इंटरव्यू या ग्रूप डिस्कशन या फिर मार्केटिंग फील्ड में अपने क्लाइंट को प्रभावित करना हो, हर जगह आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं।

होमवर्क जरूरी

अगर आप किसी संस्थान में जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो वहां अप्लाई करने से पहले या साथ-साथ उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने का प्रयास करें। मसलन यह कि कंपनी क्या काम करती है, मार्केट में उसकी छवि कैसी है, वहां के लोगों को मार्केट में कितना आदर-सम्मान दिया जाता है आदि। यह सब जानने के बाद ही आप इंटरव्यू के दौरान वहां के एचआर को बता सकते हैं कि आप वहां के लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं। 90 फीसद से ज्यादा उम्मीदवार ऐसा नहीं करते। ऐसे में इंटरव्यू के वक्त जब उनसे पूछा जाता है कि आप संस्थान की तरक्की में किस तरह का योगदान दे सकते हैं, तो उम्मीदवारों के पास तार्किक जवाब नहीं होता। फिर वे जो भी जवाब देते हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। अगर कंपनी के बारे में आपको जानकारी है, तो आप आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कह सकते हैं।

तोल-मोल कर बोलें

जब कभी इंटरव्यू के लिए जाएं, तो अपने रेज्यूमे में लिखी बातों का ध्यान रखें। अपने बारे में वही बताएं, जो आपने रेज्यूमे में पहले लिखकर भेजा है। इंटरव्यू के दौरान पूरी विनम्रता से, मीडियम टोन में अपनी बात रखें। न तो इतनी जोर से बोलें कि आपकी आवाज कमरे से बाहर तक सुनाई दे और न ही इतना धीमे बोलें कि सामने वाले लोग आपकी बात सुन ही न पाएं। अगर आपकी आवाज कर्कश, बेसुरी है, तो संगीत साधना की तरह घर पर इसे विनम्र-मधुर बनाने का रियाज करें। आगे आपको हर जगह इसका फायदा मिलता नजर आएगा।

सुनें ज्यादा, बोलें कम

इंटरव्यू या क्लाइंट मीटिंग के दौरान बीच में बोले बिना सामने वाले की बातों को गौर से सुनें। उनकी बात खत्म होने के बाद दस सेकंड सोचें और अपनी सूझ-बूझ का परिचय देते हुए विनम्रता से जवाब दें या अपनी बात रखें। एक बार जो बोलें, उसे बदलें नहीं। न ही किसी बात पर उत्तेजित हों।

संक्षिप्त समाचार

उलटफेर का शिकार हुए जोकोविच

नई दिल्ली, एजेंसी। नार्डी किसी ग्रैंड स्लैम या एटीपी मास्टर्स 1000 लेवल स्तर पर जोकोविच को हराने वाले सबसे निचली रैंकिंग के खिलाड़ी हैं। इससे पहले 122वें नंबर के केविन एंडरसन ने 2008 में मियामी में हराया था। इटली के 20 साल के लुका नार्डी ने यहां बीएनपी परिबास ओपन के तीसरे दौर में अपने बचपन के आदर्श और शीर्ष वरीय 24 बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 6-4, 3-6, 6-3 से पराजित किया। दुनिया के 123वीं रैंकिंग के नार्डी ने नंबर एक जोकोविच को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। जीत के बाद उन्होंने अपना रैकेट फेंक दिया और चेहरे को हाथों से ढाप लिया। बाद में उन्होंने कहा कि यह तो चमत्कार है। मैं सिर्फ बीस साल का हूं और रैंकिंग सौ से ज्यादा है और मैंने नोवाक को हरा दिया। नार्डी किसी ग्रैंड स्लैम या एटीपी मास्टर्स 1000 लेवल स्तर पर जोकोविच को हराने वाले सबसे निचली रैंकिंग के खिलाड़ी हैं। इससे पहले 122वें नंबर के केविन एंडरसन ने 2008 में मियामी में हराया था।

नार्डी ने जोकोविच को सोमवार को तीसरे दौर में हराकर चौंका दिया। इस हार के साथ ही जोकोविच की टूर्नामेंट में रिकॉर्ड छठे खिताब की दावेदारी समाप्त हो गई। 2024 में अभी तक जोकोविच कोई खिताब नहीं जीत पाए हैं। इससे पहले जनवरी में उन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन में यानिक सिनर से सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था।

मैच के दौरान जोकोविच की नार्डी और अंपायर से बहस भी देखने को मिली। इनके बीच शॉट में लग रहे टाइम को लेकर बातचीत हुई। हालांकि, अंपायर ने नार्डी का पक्ष लिया। इस विवाद के बावजूद, जोकोविच इतालवी खिलाड़ी को हराने में कामयाब नहीं हो पाए। नार्डी ने अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की।

मुशीर खान ने तोड़ा सचिन का 29 साल पुराना रिकॉर्ड

मुंबई, एजेंसी। मुशीर खान ने यहां वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ के खिलाफ रणजी ट्रॉफी फाइनल में शतक बनाने वाला सबसे युवा मुंबई बल्लेबाज बनकर महान सचिन तेंदुलकर का 29 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 19 साल 14 दिन की उम्र में मुशीर ने फाइनल में मुंबई की दूसरी पारी में 255 गेंदों में शतक बनाया। वहीं सचिन ने अपने

22वें जन्मदिन से एक महीने पहले 1994/95 सीजन में पंजाब के खिलाफ दो शतक बनाकर रणजी फाइनल में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के मुंबई बल्लेबाज होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था, जिससे मुंबई को खिताब जीतने में मदद मिली। संयोग से, जिस समय मुशीर ने यह उपलब्धि हासिल की। उस समय सचिन भी स्टैंड में मौजूद थे और इस युवा खिलाड़ी को अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए देख रहे थे।

दूसरे दिन के खेल में मुंबई ने पहली पारी में 119 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। मुशीर और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने मुंबई की लड़खड़ाई पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने अपने-अपने अर्धशतक पूरे किए, जिससे स्कोर दो विकेट पर 141 रन हो गया। तीसरे दिन रहाणे के 73 रन पर आउट होने के बाद मुशीर ने श्रेयस अय्यर के साथ रन बनाना जारी रखा। मैच के 90वें ओवर में मुशीर ने तीन मैचों में अपना दूसरा प्रथम श्रेणी शतक हासिल किया।

टी20 वर्ल्ड कप का खरा सोना हैं विराट कोहली

नईदिल्ली, एजेंसी। इसी साल जून में होने वाली टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय रन मशीन विराट कोहली के खेलने पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मंगलवार को जब ये खबरें आईं कि सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट कोहली को विश्व कप टीम से ड्रॉप करने पर विचार कर रहे हैं तो क्रिकेट प्रशंसकों को यह बात हजम नहीं हुई। चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट कोहली को विश्व कप टीम से बाहर रखने की भले ही कोई वजह बताएं, लेकिन हकीकत ये है कि यह खिलाड़ी इस मेगा इवेंट का खरा सोना है।

2022 टी20 विश्व कप के पहले मैच में खेली थी मैच जिताऊ पारी

टी20 विश्व कप में विराट कोहली के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उनके जैसा प्लेयर इस टूर्नामेंट में कभी भी फीका नहीं रह सकता। पिछले टी20 विश्व कप से पहले भी विराट को टीम में रखने पर कई बातें हो रही थीं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही मैच में उन्होंने जो मैच जिताऊ पारी खेली थी उसने सभी के मुंह बंद कर दिए थे। विराट ने इस मेगा इवेंट में कई बार यह साबित किया है कि वह इस फटाफट क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं।

टी20 वर्ल्ड कप में विराट के बेहतरीन आंकड़े

सबसे ज्यादा अर्धशतक विराट के नाम

इस मेगा इवेंट में विराट कोहली के नाम सबसे अधिक अर्धशतक का रिकॉर्ड दर्ज है। कोहली ने टी20 विश्व कप में कुल 14 अर्धशतक लगाए हैं। उनके बाद क्रिस गेल हैं जिन्होंने 9 हाफ सेंचुरी लगाई हैं।

सबसे ज्यादा रन कोहली के नाम

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन भी विराट कोहली के नाम हैं। कोहली ने 27 मैचों में 81.5 की औसत से 1141 रन बनाए हैं। दूसरे स्थान पर महेला जयवर्धने हैं जिन्होंने 1016 रन बनाए हैं।

बेस्ट स्ट्राइक रेट और बेस्ट औसत विराट के नाम

टी20 विश्व कप में विराट कोहली बेस्ट स्ट्राइक रेट और बेस्ट औसत वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। इस मेगा इवेंट में कोहली का औसत 81.5 का और स्ट्राइक रेट 131.30 का है।

नॉकआउट मैचों में भी है विराट का दबदबा

विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बैं। इसके अलावा नॉकआउट में कोहली ने ही सबसे अधिक फिफ्टी भी लगाई है। नॉकआउट मैचों में बेस्ट औसत भी विराट कोहली का है। इसके अलावा विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप में दो बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है जो सबसे अधिक है। कोहली ने 2014 और 2016 में यह खिताब जीता था।

डब्ल्यूपीएल 2024

एलिसे पेरी के शानदार ऑल-राउंड प्रदर्शन से आरसीबी को मुंबई इंडियंस को हराया

नई दिल्ली, एजेंसी। यहां के अरुण जेटली स्टेडियम में मंगलवार को महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2024 के 19वें मैच में एलिसे पेरी ने मध्यम गति की गेंदबाजी का शानदार प्रदर्शन करते हुए 6-15 का शानदार स्कोर बनाया और शानदार नाबाद 40 रन बनाए, जिससे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) ने गत चैंपियन मुंबई इंडियंस को 30 गेंद रहते सात विकेट से हरा दिया।इस जीत के साथ आरसीबी ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली, जिससे गत चैंपियन मुंबई इंडियंस की डब्ल्यूपीएल के फाइनल में सीधे जगह बनाने की संभावना को नुकसान पहुंचा। मुंबई इंडियंस की हार ने तालिका में शीर्ष पर मौजूद दिल्ली कैपिटल्स को खुशी दी, क्योंकि अब उन्हें गुजरात जायंट्स के खिलाफ अपना अगला मैच जीतने की जरूरत है। इस जीत से दिल्ली को 12 अंक हासिल करने और फाइनल में अपनी जगह पक्की करने में मदद मिलेगी। दिल्ली कैपिटल्स की एक बड़ी हार से उनके 10 अंक हो जाएंगे।

आरसीबी के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करने के बाद मुंबई इंडियंस मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने पहले विकेट के लिए 43 रन जोड़े। हेले मैथ्यूज 26 रन बनाकर सोफी डिवाइन की गेंद पर पेरी के हाथों कैच आउट हो गईं। इसके बाद पेरी ने सजीवन सजना को 30 रन पर आउट कर दिया।

नौवें ओवर में दो गेंदों पर दो विकेट गिरने से मुंबई इंडियंस का स्कोर 65/3 हो गया और 11वें ओवर में चार रन बाद अमेलिया केर आउट हो गईं। यह सिलसिला जारी रहा, क्योंकि वे लगातार विकेट खोते रहे, क्योंकि पेरी ने लगातार छह विकेट लेकर 6-15 के साथ समाप्त किया। मुंबई इंडियंस केवल 113 रन ही बना सकी, जिससे आरसीबी मजबूत स्थिति में रही।

जवाब में आरसीबी की शुरुआत खराब रही और बोर्ड पर 22 रन के स्कोर पर सोफी मोलिनक्स नौ रन पर आउट हो गईं। कप्तान स्मृति मंधाना भी 13 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गईं। सोफी डिवाइन भी जल्दी आउट हो गईं और सातवें ओवर में आरसीबी 39/3 पर संकट में थी।एलिसे पेरी और ऋचा घोष ने चौथे विकेट के लिए 76 रन बनाकर आरसीबी को मैच जीतने में मदद की।पेरी ने 38 गेंदों में नाबाद 40 रन बनाए और ऋचा घोष ने 28 गेंदों में 36 रन बनाए। आरसीबी ने बहुत कुछ बचाते हुए मैच जीत लिया।

पेरी ने पांच चौके और एक छक्का लगाया, जबकि ऋचा घोष, जिन्हें नेट साइवर-ब्रंट द्वारा गिराए जाने के बाद शुरुआती राहत मिली, उन्होंने चार चौके और दो छक्के लगाए। इसके बाद उन्होंने 43 गेंदों में अपनी चौथे विकेट की साझेदारी में अर्धशतक पूरा किया, जिसमें पेरी ने 15 रन और ऋचा घोष ने 28 रन का योगदान दिया।संक्षिप्त स्कोर-मुंबई इंडियंस 19 ओवर में 113 रन पर ऑल आउट (सजीवन सजना 30, हेले मैथ्यूज 28; एलिसे पेरी 6-15) रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से 15 ओवर में 115/3 से हार गई (एलिसे पेरी 40 नाबाद, ऋचा घोष 36 नाबाद) सात विकेट से।

मोहम्मद नाबी के तूफान में उड़ा आयरलैंड, अफगानिस्तान ने तीसरा वनडे 117 रन से जीत सीरीज की अपने नाम

अफगानिस्तान- आयरलैंड

शारजाह, एजेंसी। अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का अंतिम और तीसरा मुकाबला 12 मार्च को यूएई के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में पूरी तरह से अफगानिस्तान का दबदबा देखने को मिला।

अफगानिस्तान ने दमदार प्रदर्शन किया और 117 रन से मैच अपने नाम कर लिया। इस बड़ी जीत के साथ अफगानिस्तान 2-0 से यह सीरीज भी जीतने में कामियाब रही। आखिर तीसरे वनडे में क्या-क्या हुआ, आइये विस्तार से जानते हैं। अफगानिस्तान टीम टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरी

थी। ऐसे में उन्होंने 9 विकेट पर निर्धारित 50 ओवर में 236 रन बोर्ड पर लगा दिए। अफगानिस्तान की तरफ से हशमातुल्लाह शाहिदी ने सर्वाधिक 69 रन बनाए। इसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज ने भी 51 रन की अच्छी पारी खेली। वहीं अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नाबी ने भी 48 रन ठोके।

मोहम्मद नाबी के सामने आयरलैंड ने टेके घुटने

237 रन के टारगेट का पीछा करते हुए मेहमान टीम आयरलैंड पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 35 ओवर में ही 119 रन बनाकर ढेर हो गई। इस तरह अफगानिस्तान तीसरा वनडे 117 रन से जीत गई। आयरलैंड को ऑल आउट करने में बल्ले से कमाल करने वाले मोहम्मद नाबी ने अहम भूमिका निभाई। नाबी ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 विकेट लिए। इसके अलावा नांगेयलिया खारोटे ने 4 जबकि फजलहक फारूकी ने 1 विकेट लिया। नाबी को उनके दमदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से भी नवाजा गया।

आल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप

दूसरे दौर में पहुंचीं सिंधू, विपक्षी खिलाड़ी के रिटायर होने पर हुआ फायदा

बर्मिंघम, एजेंसी। भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू बर्मिंघम में चल रहे ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। उनका मुकाबला जर्मनी की यिवोनी ली से था। हालांकि, यिवोनी ली मैच के दौरान चोटिल हो गई हैं और उन्होंने मैच से नाम वापस लेने का फैसला किया। उनके मैच से रिटायर होने से सिंधू को फायदा हुआ। वहीं, पुरुष एकल में एचएस प्रणय और किदांबी श्रीकांत को पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। पूर्व विश्व चैंपियन और दुनिया की 11वें नंबर की खिलाड़ी सिंधू ने पहला गेम 21-10 से जीता जिसके बाद दुनिया की 26वें नंबर की खिलाड़ी ली ने मुकाबले से हटने का फैसला किया। हैदराबाद की 28 साल की सिंधू अगले दौर में कोरिया की शीर्ष वरीय आन से यंग से भिड़ेंगी जिनके खिलाफ उन्होंने अब तक सभी छह मुकाबले गंवाए हैं।

सिंधू दुनिया की नंबर एक कोरियाई खिलाड़ी के खिलाफ सिर्फ एक बार गेम जीतने में सफल रही हैं और उन्होंने पिछले साल दुबई में एशियाई चैंपियनशिप के दौरान दोनों खिलाड़ियों के बीच पिछली बार हुए मुकाबले में ऐसा किया था। दाएं घुटने की चोट से उबर रहीं आन से ने रविवार को फ्रेंच ओपन के रूप में सत्र का अपना दूसरा खिताब जीता था।

सिंधू ने ली के खिलाफ अच्छी शुरुआत की और 4-4 के स्कोर के बाद लगातार अंक बनाते हुए ब्रेक तक 11-7 से आगे हो गईं। भारतीय खिलाड़ी ने इसके बाद भी आसानी से अंक जुटाए। ली ने नेट पर सर्विस मारकर सिंधू को प्वाइंट दिए। जर्मनी की खिलाड़ी ने इसके बाद बाहर शॉट मारकर पहला गेम सिंधू की झोली में डाल दिया था।

प्रणय-श्रीकांत हारे

दुनिया के आठवें नंबर के खिलाड़ी प्रणय को पहले गेम में बढ़त मिलने के बावजूद चीनी ताइपे के 32वीं रैंकिंग के सु ली यांग के खिलाफ 21-14 13-21 13-21 से हार का सामना करना पड़ा। श्रीकांत, जो पेरिस ओलंपिक में जगह बनाने के लिए जूझ रहे हैं, शीर्ष वरीयता प्राप्त और दुनिया के नंबर एक विक्टर एक्सेलसन के खिलाफ 9-21 9-21 से हार गए।

अरुण गोविल ने

रणबीर कपूर को बताया संस्कारी बच्चा

नितेश तिवारी के प्रोजेक्ट 'रामायण' को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है। इसमें भगवान राम के रोल के लिए रणबीर कपूर का नाम सामने आया है। वहीं उनके साथ यश और साई पल्लवी भी होने की खबर है। अब रणबीर कपूर के श्री राम का किरदार निभाने पर टीवी की 'रामायण' के राम अरुण गोविल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसपर अपने विचार रखे हैं कि क्या रणबीर इस किरदार को बखूबी निभा पाएंगे या नहीं। मीडिया के साथ बात करते हुए अरुण गोविल ने कहा है कि रणबीर कपूर इस रोल में हिट होंगे या नहीं ये नहीं पता, लेकिन रणबीर एक्टर बहुत अच्छे हैं। अरुण ने कहा,फिल्म के रोल हिट होंगे या नहीं वो तो समय बताएगा। पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जहां तक रणबीर की बात है तो वह एक अच्छे और मेहनती एक्टर हैं। वह कई अवॉर्ड जीत चुके हैं। मैं उनको जितना जानता हूं, वह एक बहुत संस्कारी बच्चे हैं। वह ईमानदारी एक्टर है उनके अंदर संस्कार, संस्कृति है। मुझे लगता है वो ये रोल अच्छे से निभाएंगे। बता दें कि अरुण गोविल ने रामानंद सागर की 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभाया था और आज तक लोग उन्हें उसी रूप में देखते हैं। अयोध्या में हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अरुण गोविल, ऑनस्क्रीन सीता दीपिका चिखलिया और लक्ष्मण सुनील लहरी के साथ पहुंचे थे। उनके दर्शन के लिए वहां लोगों की भीड़ उमड़ गई थी।

आमिर खान अपनी आने वाली फिल्म पर बोलें

तारे ज़मीन पर ने आपको रुलाया है, सितारे ज़मीन पर...

आमिर खान देश के फेवरेट सुपरस्टार्स में से एक हैं। अब तक उन्होंने हमेशा अपने फैन्स और ऑडियंस को उनके स्क्रिप्ट चुनाव से हैरान किया हैं और उनकी सुपर से भी ऊपर परफॉर्मेंस ने भी लेवल को और बढ़ाया है। हालांकि इन दिनों जबकि मिस्टर परफेक्शनिस्ट खान अपने प्रोडक्शन बैनर के तले बनी फिल्म लापता लेडीज को लेकर चर्चा में लगातार बने रहे हैं, जो पूरे देश में धूम मचा रही है क्योंकि फिल्म को हर तरफ से पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिली है, वहीं एक्टर अपने अलगे प्रोजेक्ट सितारें जमीन पर में अपनी एक्टिंग के साथ ऑडियंस को फिर से सरप्राइज करने की तैयारी में भी जुटे हैं।

आमिर खान , आमिर खान प्रोडक्शंस के सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव थे, जहां उन्होंने फैंस और दर्शकों के साथ लापता लेडीज और सितारे ज़मीन पर पर खुलकर बात की। सोशल मीडिया इंटरैक्शन सेशन के दौरान, आमिर खान ने सितारे ज़मीन पर से रोमांचक जानकारियाँ शेयर की और कहा कि फिल्म क्रिसमस के आसपास सिनेमाघरों में रिलीज़ की जाएगी। फिल्म के बारे में डिटेल में बात करते हुए, सुपरस्टार ने एक बड़ा खुलासा किया और कहा कि सितारे ज़मीन पर एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है।

आशा भोसले ने किया

पोती जनाई के बॉलीवुड डेब्यू का ऐलान

दिग्गज गायिका आशा भोसले की पोती जनाई भोसले फिल्मों में डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वह फिल्म निर्माता संदीप सिंह की फिल्म 'छत्रपति शिवाजी महाराज' में नजर आने वाली हैं। फिल्म में वह छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी रानी साई भोंसले की भूमिका निभाती नजर आएंगी।

आशा भोसले ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए खुशी जाहिर की है। उन्होंने लिखा,मैं अपनी प्यारी पोती जनाई भोसले को आने वाली 'छत्रपति शिवाजी महाराज' में सिनेमा जगत से जुड़ते हुए देखकर वास्तव में बहुत खुश हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वह सिनेमाई इतिहास में अपनी जगह बनाएगी और मैं उन्हें और संदीप सिंह को शुभकामनाएं देती हूं। संदीप सिंह ने भी जनाई को अपनी फिल्म में कास्ट करने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा,मैं जनाई को लॉन्च करते हुए बहुत सम्मानित और प्राउड महसूस कर रहा हूं,जो ब्रिलिएंट परिवार का हिस्सा हैं। दिवंगत लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी की पोती हैं। वह एक प्राउड भोसले हैं, जिन्हें पहले से ही भावपूर्ण आवाज का उपहार मिला हुआ है और संगीत का भी शौक है।

संक्षिप्त समाचार

पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को राहत, घरों पर नहीं चलेगा डीडीए का बुलडोजर

नईदिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं करेगा। ये शरणार्थी 2011 से यमुना बाढ़ के मैदानों में रह रहे हैं। हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें डीडीए के चार मार्च को जारी नोटिस को चुनौती दी गई। नोटिस के अनुसार, निवासियों को 6 मार्च तक जगह खाली करने को कहा गया था। अब हाईकोर्ट ने डीडीए को एक्शन नहीं लेने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने मजनूं का टीला में रहने वाले 800 शरणार्थियों के लिए वैकल्पिक आवास का इंतजाम होने तक डिमॉलिशन पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की थी। लाइव लॉ के अनुसार, कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। डीडीए ने चार मार्चको एक सार्वजनिक नोटिस चिपकाया था जिसमें निवासियों को छह मार्च तक शिविर खाली करने के लिए कहा गया था। ऐसा नहीं करने पर उन्हें गिरा दिया जाएगा। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कई सालों से मजनूं का टीला में रह रहे हैं और अधिकारी उन्हें बेसिक सुविधाएं भी दे रहे हैं। 29 जनवरी को नेशनल ग्रीम ट्रिब्यूनल के यमुना बाढ़ क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के आदेश पर कार्रवाई करते हुए डीडीए ने निवासियों को घर खाली करने का नोटिस दिया था। अब 19 मार्च को इस मामले पर सुनवाई होगी।

डांस फ्लोर पर 4 लड़कों ने घेरा और करने लगे छेड़छाड़, पीटा भी; गुरुग्राम के क्लब में बवाल

नईदिल्ली, एजेंसी। एक क्लब में डांस फ्लोर के विवाद में चार लोगों ने दंपत्ति से मारपीट की। वहीं युवकों द्वारा महिला के साथ अभद्रता किए जाने का आरोप भी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि वह सेक्टर-102 की रहने वाली है और 10 मार्च को वह अपने पति के साथ क्षेत्र के एक क्लब में गई थी। यहां क्लब में पार्टी करने के दौरान चार युवक उनके साथ अभद्रता करने लगे। जब उन्होंने विरोध किया तो आरोपियों ने न केवल उनके साथ मारपीट की बल्कि उनसे छेड़छाड़ भी की। इस बारे में उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 323, 34, 354, 354ए के तहत केस दर्ज कर लिया है। जांच के लिए क्लब में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ली है। जांच के आधार पर ही आगामी कार्रवाई की जाएगी।

ग्रेटर नोएडा के ढाबों में सुबह-सुबह लगी भीषण आग

नईदिल्ली, एजेंसी। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में कुछ ढाबों में बुधवार सुबह-सुबह भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जिसने कई ढाबों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आसमान में काले धुएं का गुबार दिख रहा है। मौके पर दमकल की आठ गाड़ियां मौजूद हैं जो आग बुझाने का काम कर रही हैं। एक दमकलकर्मी ने बताया कि बुधवार को थाना बिसरख क्षेत्र के अंतर्गत हिंडन नदी के किनारे स्थित कुछ ढाबों में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। जिसकी सूचना प्राप्त होते ही तत्काल फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों को आग बुझाने के लिए भेजा गया।

पाकिस्तानियों को ला रही भाजपा, भारी भीड़ आएगी; केजरीवाल ने सीएए को बताया खतरा

नईदिल्ली, एजेंसी। के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार प्रहार किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश में अपने लोगों को सरकार रोजगार नहीं दे रही है, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को भारत में लाया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सीएए लागू होने से भारी भीड़ भारत में आएगी और यह देश के लिए खतरनाक है।

अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महंगाई और बेरोजगारी की बजाय केंद्र सरकार सीएए की बात कर रही है। उन्होंने कहा, भाजपा की केंद्र सरकार ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी किया है। 10 साल देश पर राज करने के बाद ऐन चुनाव से पहले इन्हें सीएए की बात करनी पड़ रही है। अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज अपने काम पर वोट मांग रहे होते। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है। किसी के लिए भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी महंगाई हो रही है। उधर, हमारे युवा रोजगार के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई की बजाय सीएए की बात कर रही है।

केजरीवाल ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में लाकर बसाया जाएगा। उन्हें रोजगार और घर दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा, अजीब बात है ना, बीजेपी की सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे हैं, पाकिस्तान से लोगों को लाकर उनके बच्चों को रोजगार देंगे। भारत के ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उन्हें देना चाहते हैं। भारत सरकार का जो पैसा हमारे देश के विकास पर खर्च होना चाहिए वह पाकिस्तानियों को हमारे देश में बसाने के लिए किया जाएगा। इन तीन देशों में ढाई से तीन करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, भारी भीड़ आ जाएगी। डेढ़ करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इन्हें रोजगार, कहां बसाओगे इन्हें, बीजेपी वाले अपने घर में रखेंगे क्या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि पड़ोसी देशों से लोगों को लाकर भाजपा उन इलाकों में अपना वोट बढ़ाना चाहती है, जहां कमजोर है। उन्होंने कहा, मैंने कई लोगों से बात की, कुछ का कहना है कि यह पूरा खेल वोट बैंक बनाने का है। इन देशों से डेढ़ दो करोड़ लोगों को भारत लाया गया और उन्हें चुन-चुनकर इस तरह बसाया गया कि जहां बीजेपी के वोट कम हैं, तो वहां भाजपा का पक्का वोट बैंक बन जाएगा। भविष्य के चुनावों में भाजपा को बहुत बड़ा फायदा होगा। मुझे नहीं पता यह सच है या गलत। केजरीवाल ने कहा कि कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों से गरीबों को नहीं लाना चाहता। बीजेपी अकेली पार्टी है जो पड़ोसी देशों के गरीबों को घुसाने के लिए दरवाजा खोल रही है।

नूंह-मेवात पहुंच रहे आपके चोरी गए फोन

नईदिल्ली, एजेंसी। दिल्ली-एनसीआर से फोन छीनने के बाद झपटमार नूंह और राजस्थान में सक्रिय जालसाजों को बेच रहे हैं। उन फोन का इस्तेमाल कर जालसाज लोगों से ठगी कर रहे। गुरुग्राम साइबर पुलिस द्वारा ठगी के मामले की जांच में यह खुलासा हुआ। साइबर पुलिस अब लोगों के हाथ से छीने गए फोन की जांच कर रही, ताकि जालसाजों तक फोन पहुंचाने वाले गैंग का पता चल सके। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि छीने गए फोन के मामलों में जांच कहां तक पहुंची है। बता दें कि हरियाणा पुलिस की सख्ती के बाद जालसाजों को फर्जी सिम कार्ड और म्यूल बैंक खाते मिलना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में जालसाजों ने झपटमारों से फोन और सिम कार्ड के लिए संपर्क कर नया नेटवर्क शुरू किया। उसके बाद जालसाजों को आराम से फोन और सिम कार्ड मिलना शुरू हो गए। साइबर पुलिस इस नेटवर्क को भी तोड़ने के लिए योजना बना रही है। इसके अलावा जालसाजों ने फर्जी बैंक खाते खुलवाने के लिए कई निजी बैंक के मैनेजर और कर्मचारियों से साठगांठ कर हजारों खातों को खुलवाया। जालसाज ठगी करने के लिए समय के अनुसार अपने आप को भी तकनीकी विषयों में मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा वह सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक खातों के लिए भी अलग से नया नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। जालसाल निजी बैंक में काम करने वाले मैनेजर और कर्मचारियों को रुपयों का लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं। उन्हें 15 हजार से दो लाख रुपये तक देते हैं। इन रुपयों के लालच में बैंक मैनेजर और कर्मचारियों ने हजारों की संख्या में खातों को खोलकर जालसाजों को मुहैया करवाया है। नूंह में बैठे जालसाज ने 12 अप्रैल 2023 को झपटमार से छीने हुए सिम कार्ड का प्रयोग करते हुए फेडक्स पार्सल में गैर कानूनी गतिविधि से संबंधित होने के नाम पर डराया गया था।

दिल्ली को केंद्र सरकार देगी सौगात, दो मेट्रो कॉरिडोर को मिल सकती है मंजूरी

नईदिल्ली, एजेंसी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में अब कम ही समय बचा है। ऐसे में दिल्ली वालों को केंद्र सरकार एक बड़ी सौगात दे सकती है। माना जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट बुधवार को दो और दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे सकती है। ये दो कॉरिडोर- लाजपत नगर से साकेत में जी ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ होंगे। दोनों कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है। डीएमआरसी चौथे चरण के तहत इन कॉरिडोर का निर्माण करेगी। जिसकी लागत पर सभी ने चुप्पी साधी हुई है। यह सीधी कनेक्टिविटी देगा। लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर में जहां आठ स्टेशन होंगे। वहीं 12 किलोमीटर लंबे इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ लाइन पर 10 मेट्रो स्टेशन होंगे। टीओआई को एक सूत्र ने बताया, ये दो लाइनें ट्रेवल के समय को कम कर देंगी क्योंकि यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए (ट्रेनों से) लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ये बिजी कमर्शियल क्षेत्रों को आपस में जोड़ेंगे। एक बार परियोजनाओं को मंजूरी मिल जाए, फिर डीएमआरसी इसके लिए बोली प्रक्रिया शुरू कर देगी।

अनूप जलोटा और जसलीन मथारू की पुरानी तस्वीर गलत दावे से की जा रही है शेयर

नईदिल्ली, एजेंसी। भजन गायक अनूप जलोटा और सिंगर व अभिनेत्री जसलीन मथारू की एक तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिसमें दोनों को दूल्हा-दुल्हन की वेशभूषा में देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इस पोस्ट को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि दोनों ने शादी कर ली है।

वायरल तस्वीर साल 2020 की है और उनकी फिल्म 'वो मेरी स्टूडेंट है' के सेट की है। तस्वीर को गलत दावे से शेयर किया जा रहा है। वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने सबसे पहले इसके बारे में संबंधित कीवर्ड्स से सर्च किया। सर्च में हमें किसी भी प्रतिष्ठित मीडिया वेबसाइट पर दावे की पुष्टि करती कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने गूगल रिवर्स इमेज का इस्तेमाल किया। हमें तस्वीर पुरानी तारीख में कई न्यूज वेबसाइट पर मिली। हरजिंदगी की वेबसाइट पर 9 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित खबर में वायरल तस्वीर मिली। दी गई जानकारी के अनुसार, यह तस्वीर दोनों की फिल्म की है।

अब दिल्ली में आएगी काशी वाली फील, यहां रोज होगी यमुना आरती; डीडीए ने बनाया अद्भुत घाट

नईदिल्ली, एजेंसी। आपने बहुत से लोगों से बनारस और हरिद्वार में सुबह-शाम होने वाली गंगा आरती के बारे में जरूर सुना होगा। आपका भी मन एक बार इस नजारे को अपनी आंखों में कैद करने का होगा। अगर आपने अबतक गंगा आरती नहीं देखी है तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दिल्ली में अब रोजाना इसे देखने को आनंद उठा सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंगलवार को वासुदेव घाट का उद्घाटन किया और आरती की। यह यमुना घाट और निगम बोध घाट के बीच यमुना के पश्चिमी तट पर स्थित है।

इस घाट को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा बनाया गया है। पहले यहां खड़ी ढलान और कचरे की वजह से लोग नहीं आते थे। पिछले साल जुलाई में आई बाढ़ की वजह से यहां 1.5 फुट गहरी गाद जमा हो गई। डीडीए ने तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इसे रिस्टोर किया। यहां नक्काशीदार मंडप, ट्यूलिप, गेंदा और सदाबहार के मौसमी फूलों की क्यारियां लगाई। इसके अलावा यहां 2,000 से ज्यादा देशी और प्राकृतिक पेड़ और 4,00,000 नदी घास के पौधे लगाए गए हैं।

145 मीटर के घाट में 150 कारों के लिए पार्किंग की जगह के साथ तीन एंट्री प्वाइंट हैं। यहां नदी तक उतरने के लिए 25 सीढ़ियां बनाई गई हैं। घाट पर मां यमुना की एक प्रतिमा स्थापित की गई है, साथ ही उत्तर प्रदेश के जलेसर से मंगवाई गई 300 किलोग्राम की यूनिक (अनोखी) मेटल बेल भी लगाई गई है, जिसे बजाने पर एक वाइब्रेशन और ध्वनि पैदा होती है। डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाट का नाम सुझाया था। घाट का उद्घाटन करते हुए एलजी सक्सेना ने कहा, मुझे विश्वास है कि इस घाट से न केवल यमुना के तटों को अपना पुराना स्वरूप वापस मिलेगा बल्कि लोगों को यहां आकर सुखद अनुभूति भी होगी। यमुना किसी एक धर्म, व्यक्ति या सरकार की नहीं है। यह एक जीवनदायिनी और हम सबकी है। अधिकारियों ने बताया कि डीडीए ने एक पंजीकृत सोसायटी के साथ एक एमओयू साइन किया है, जो नियमित रूप से घाट पर यमुना आरती का आयोजन करेगी और साइट का रखरखाव भी करेगी।

चाचा बने प्रधानमंत्री, तो पाकिस्तान लौट आए भतीजे; 6 साल हुई बाद नवाज शरीफ के बेटों की घर वापसी

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान की सत्ताधारी मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के सुप्रीम लीडर नवाज शरीफ के बेटे हुसैन और हसन छह साल बाद मंगलवार को देश लौट आए। हुसैन और हसन की पाकिस्तान वापसी ऐसे समय में हुई है जब उनके चाचा शहबाज शरीफ ने पहली बार चुनाव जीतकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली है।

2016 के पनामा पेपर्स घोटाले में नाम आने के बाद हसन नवाज और हुसैन नवाज ने 2018 में पाकिस्तान छोड़ दिया था। यह मामला शरीफ परिवार के पास लंदन में शानदार अपार्टमेंट होने से संबंधित है। एक जवाबदेही अदालत ने उन्हें 2018 में एवेनफिल्ड मामले में अपराधी घोषित किया था और उनके खिलाफ गैर-जमानती स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वे लंदन चले गए थे। हालांकि जवाबदेही अदालत ने पनामा पेपर्स घोटाले में उनकी गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया है।

सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी ने एक बयान में कहा, ''नवाज के बेटे मंगलवार को लंदन से यहां पहुंचे और उन्हें कड़ी सुरक्षा में उनके 'जाति उमरा लाहौर' स्थित उनके घर ले जाया गया। नवाज शरीफ पीएमएल-एन के प्रमुख हैं। शरीफ परिवार के 'जाति उमरा' आवास को पहले ही मुख्यमंत्री आवास घोषित किया जा चुका है, जहां पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज और उनके पिता नवाज शरीफ की सुरक्षा और प्रोटोकॉल के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

हुसैन और हसन ने अपने वकील के माध्यम से इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत में आवेदन किया और एवेनफील्ड अपार्टमेंट, अल-अजीजिया और 'फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट' मामलों में उनके खिलाफ जारी वारंट को निलंबित करने का अनुरोध किया जिसे स्वीकार कर लिया गया। पिछले हफ्ते अदालत ने पनामा पेपर्स घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के तीन मामलों में उनके गिरफ्तारी वारंट को 14 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया था।

एलेक्सी नवलनी के सहयोगी पर जानलेवा हमला, हमलावरों ने हथौड़े से किया वार

वारसॉ , एजेंसी। रूसी राष्?ट्रपति व्?लादिमीर पुतिन के कट्टर विरोधी माने जाने वाले विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की मौत के बाद अब उनके सहयोगियों पर जान का खतरा मंडरा रहा है। एलेक्सी नवलनी के करीबी और सहयोगी माने जाने वाले लियोनिद वोल्कोव पर मंगलवार को लिथुआनिया में उनके घर के बाहर हमला किया गया।

नवलनी की प्रवक्ता किरा यर्मिश ने कहा, ÷लियोनिद वोल्कोव पर उनके घर के बाहर हमला किया गया है। किसी ने कार की खिड़की तोड़ दी और उनकी आंखों में आंसू गैस फेंक दी, जिसके बाद हमलावर ने लियोनिद को हथौड़े से मारना शुरू कर दिया।÷ वोल्कोव की चोटों की कुछ तस्वीर भी साझा की गई। तस्वीर में देखा जा सकता है कि वोल्कोव की आंख काली पड़ चुकी है। उसके माथे पर एक लाल निशान है। वहीं, उनके पैर से खून बह रहा है। वोल्कोव नवलनी के करीबी सहयोगी थे, जो 2023 तक दिवंगत नेता के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ और उनके भ्रष्टाचार विरोधी फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। एलेक्सी नवलनी की पत्नी यूलिया ने दावा किया है कि उनके पति को जहर दिया गया था। उन्होंने अपने पति की मौत के लिए राष्ट्रपति पुतिन को जिम्मेदार ठहराया। यूलिया ने कहा कि हम एलेक्सी की शहादत को बेकार जाने नहीं दे सकते और हम लगातार डटकर खड़े रहेंगे।

यूक्रेन को 30 करोड़ डॉलर का नया हथियार पैकेज भेजेगा अमेरिका

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका यूक्रेन को 30 करोड़ डॉलर (23.4 करोड़ पाउंड) के सैन्य हथियार भेजेगा, जिसमें गोला-बारूद, रॉकेट और विमान भेदी मिसाइलें शामिल हैं। मीडिया रिपोर्टों में व्हाइट हाउस के हवाले से यह बात कही गई है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को अमेरिकी कांग्रेस में इस संबंध में एक विधेयक पेश कर उस पर चर्चा की गई।

अमेरिका लगभग तीन महीने बाद यूक्रेन की मदद के लिए कोई शिपमेंट भेजेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि यह सहायता यूक्रेन की युद्धक्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, यह गोला-बारूद यूक्रेन की बंदूकों को कुछ समय के लिए रुकने नहीं देगा, लेकिन काफी कम समय

के लिए। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस कई महीनों से कांग्रेस से एक बजट पारित करने की अपील कर रहा है, जिसमें यूक्रेन के साथ-साथ इज़रायल और ताइवान को भी सहायता दिये जाने की बात है। 60 अरब डॉलर का सहायता बिल पहले ही सीनेट में पारित हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रतिनिधि सभा में इसे मतदान के लिए नहीं रखा गया है। सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने अब तक सीनेट विधेयक पर विचार करने से इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रम्प के सहयोगी जॉनसन ने कहा है कि सदन अपने स्वयं के सहायता विधेयक पर मतदान करेगा, लेकिन केवल कांग्रेस द्वारा अमेरिकी आव्रजन प्रणाली में सुधार करने वाला बजट पारित करने के बाद। मंगलवार का हथियारों और उपकरणों का आपातकालीन पैकेज यूक्रेन के पहले के हथियार अनुबंधों में की गई लागत बचत से वित्त पोषित है। सहायता की घोषणा तब हुई जब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए समर्थन दिखाने के लिए व्हाइट हाउस में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा और प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की मेजबानी की। बैठक के बाद, टस्क ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जॉनसन पहले से ही जानते हैं कि, उनके व्यक्तिगत निर्णय पर, लाखों लोगों का भाग्य निर्भर करता है। पोलिश प्रधानमंत्री ने कहा, यह कोई राजनीतिक झड़प नहीं है जो केवल अमेरिका में ही मायने रखती है। जॉनसन के इस सकारात्मक निर्णय की अनुपस्थिति वास्तव में (यूक्रेन में) हजारों लोगों की जान ले लेगी। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को डेनमार्क ने घोषणा की कि वह यूक्रेन को लगभग 33.6 करोड़ डॉलर का गोला-बारूद भेजेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमर ज़ेलेंस्की ने पिछले महीने कहा था कि हथियारों की कृत्रिम कमी के कारण देश ने हाल के महीनों में युद्ध में अपनी पकड़ खो दी है।

अमेरिका में गर्ल्स गैंग ने 66 करोड़ के कॉस्मेटिक्स चुराए

वॉशिंगटन , एजेंसी। अमेरिकी पुलिस ने मेक-अप का सामान चुराने वाले गैंग की लीडर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा- तीन बच्चों की मां 53 साल की मिशेल मैक ने 66 करोड़ रुपए के कॉस्मेटिक्स चुराए और फिर इन्हें ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेजन पर बेच दिया।

पुलिस के मुताबिक, मिशेल ने चोरी को अंजाम देने के लिए 12 लड़कियों को हायर किया था। ये सभी सेफोरा, लेंस क्राफ्टर, अल्टा, टीजे मैक्स, वालग्रीन्स जैसे लग्जरी कॉस्मेटिक्स स्टोर में जाती थीं और मेक-अप का सामान चुराती थीं। इसके बाद मिशेल डिस्काउंट पर ये सामान बेच देती थी। इस गैंग ने कैलिफोर्निया, ओहायो, टेक्सास, फ्लोरिडा समेत 10 अमेरिकी राज्यों में चोरी की। यही वजह है कि गैंग को कैलिफोर्निया गर्ल्स का नाम दे दिया गया। पुलिस ने 12 मार्च को मिशेल के घर रेड की थी। इस दौरान उन्हें 24.86 करोड़ रुपए के कॉस्मेटिक्स मिले थे। 4,500 स्कवायर फीट में बने इस घर की कीमत 2.90 करोड़ रुपए है। ब्रिटिश मीडिया डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस 2 साल से इस गैंग को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। पुलिस को इस मामले में लीड तब मिली जब गैंग की दो लड़कियों को कॉस्मेटिक ब्रैंड अल्टा के स्टोर से गिरफ्तार किया गया।

स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रकः- देवेन्द्र मालवीय द्वारा श्री सिंध्दी विनायक प्रिंटर्स 26 बी देशबंधु परिसर प्रेस काम्प्लेक्स झोन 1 एम पी नगर भोपाल म.प्र. से मुद्रित एवं 773 / 19 मेघदूत नगर इंदौर म.प्र. से प्रकाशित सम्पादक डॉ. देवेन्द्र मालवीय

कार्यालय पताः- 435 ऑर्बिट मॉल विजय नगर, इंदौर मध्यप्रदेश मोः- 98276-22204 सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र इंदौर रहेगा।

दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त सूचनाए, विचार, आलेख विभिन्न समाचार के स्त्रोत एवं संकलन लेखकों के व संकलनकर्ता के स्वंय जिनका संकलन विभिन्न एजेंसियों, के माध्यम से किया गया है, अतः समस्त प्रकार के प्रकाशन हेतु संपादक, प्रकाशक, मुद्रक का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहमत होना अनिवार्य नही है।